सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 184, नई दिल्ली । शुक्रवार, 13 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जिसकी फिरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान।

03 केजरीवाल की पांच गारंटियों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी

06 डिजिटल साक्षरता क्या है और शिक्षा में इसकी भूमिका क्या है?

08 एक शाम गौमाता के नाम विशाल भजन संध्या में झूमे गोभक्त

विशेष परिवहन आयुक्त आईएएस शहजाद आलम की तानाशाही के खिलाफ लिखा गृह मंत्री को पत्र

संजय बाटला

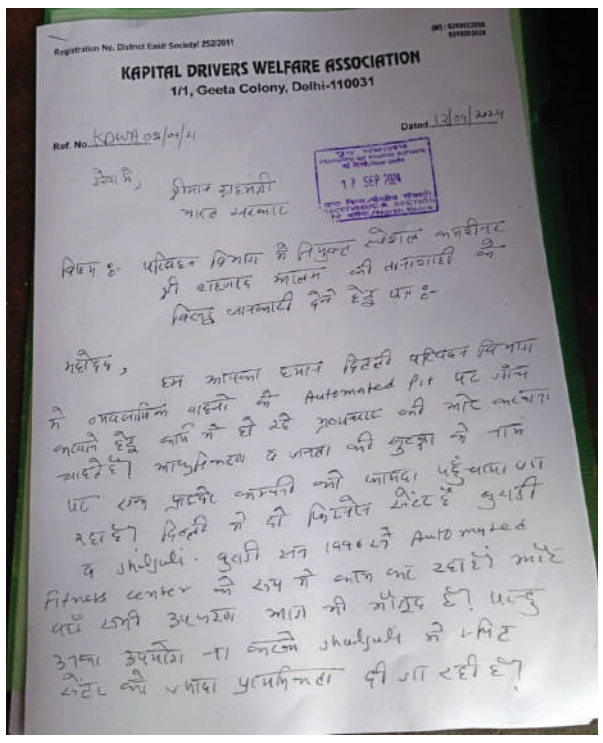

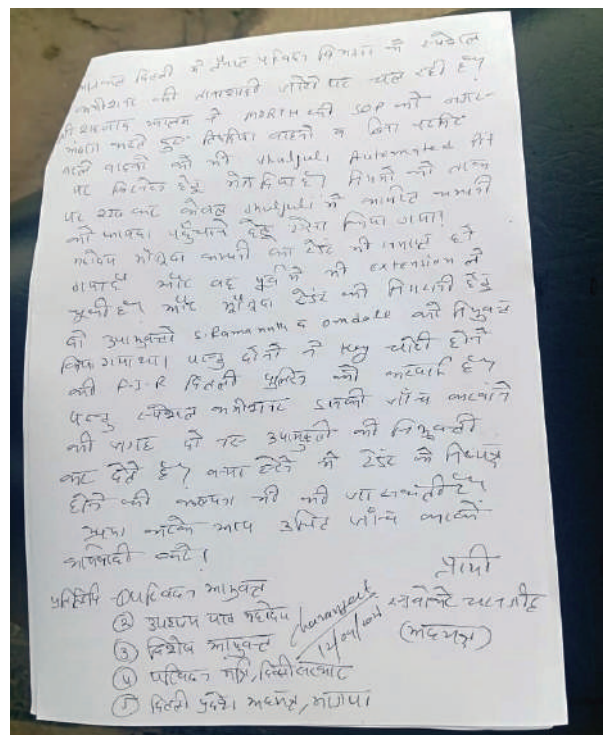

नई दिल्ली। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ साथ अब केपिटल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम के तानाशाही रवैए और उनके द्वारा जारी नियमांविरुद्ध आदेशों, दिशा निर्देशों और एडवाइजरी के खिलाफ आज भारत सरकार के गृह मंत्री और उपराज्यपाल दिल्ली के कार्यालयों में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन ने ट्विटर के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी। दोनो एसोसिएशन द्वारा दर्ज़ की गई शिकायतो में एक बात सामान्य है और वह यह की विशेष परिवहन आयुक्त प्राईवेट कम्पनी और अपने निम्न स्तरीय उपायुक्त अधिकारियो को फायदा पहुंचाने के लिए तथ्यों, आदेशों की जांच करने की जगह, जनहित की बात को समझने की जगह बेखौफ आदेश जारी कर रहे हैं। ताजा मुद्दा है दिल्ली के व्यावसायिक वाहनों जिनकी जांच बुराड़ी क्षेत्र के कार्यालय में होती आ रही है को प्राईवेट कम्पनी जिसका टैंडर खत्म हुए जमाना हो चुका को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से वाहनों की जांच झूलझूली क्षेत्र कार्यालय में करने के निर्देश जारी कर दिए। झूलझूली क्षेत्र में बने जांच शाखा में ऑटोमैटिक जांच मशीनें जिस कम्पनी की लगी हुई है उसका एग्रीमेंट के अनुसार कार्य का समय समाप्त हो चुका है और उसे विशेष परिवहन आयुक्त दो बार एक्सटेंशन दे चुका है और उस कम्पनी को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बुराड़ी शाखा के लिए जारी टैंडर को ठंडे बस्ते में डाल चुका है। **यहां जानने योग्य बात यह है की व्यावसायिक गतिविधि में शामिल सभी श्रेणी के वाहनों में से ऐसी श्रेणी के वाहन भी है जिन्हे ऑटोमेटिक वाहन जांच की आवश्यकता नहीं है या यह कह सकते हैं की ऑटोमेटिक वाहन जांच मशीन से उनकी जांच हो ही नहीं सकती** ऐसी श्रेणी के वाहनों को ऑटोमेटिक टैस्ट जांच के नाम पर झूलझूली जांच शाखा में भेजने का अर्थ स्पष्ट है प्राईवेट कम्पनी को गैर कानूनी तरीके से फ़ायदा पहुंचाना और इसी की निस्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच करवाने की मांग की है। आपकी जानकारी हेतु बता दें तीन पहिया सवारी वाहन, इलैक्ट्रिक वाहन, गार्बेज वाहन, बिना परमिट वाले वाहन और क्रेन ऑटोमैटिक जांच मशीन पर जांच के दायरे में नहीं आते फिर उनको झूलझूली जांच शाखा में भेजने के आदेश क्यों ?

सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी में कर सकती है बदलाव

परिवहन विशेष न्यूज

देश में कार को स्क्रैप में देने के लिए पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करने का नियम फिलहाल लागू है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन सचिव की राय इस नीति से थोड़ी अलग है। उनके मुताबिक सरकार किसी भी वाहन को उसकी उम्र के बजाय उसके प्रदूषण स्तर के आधार पर स्क्रैप में भेजने के बारे में सोच रही है। विशेषज्ञ इसे सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के यू-टर्न के तौर पर देख रहे हैं।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) की सालाना बैठक में अनुराग जैन ने कहा, 'लोगों ने हमसे पूछा कि अगर वे वाहन का रखरखाव अच्छे से कर रहे हैं तो स्क्रैपिंग अनिवार्य क्यों होनी चाहिए? इसके बाद इस बात की संभावना तलाशी जा रही है कि क्या वाहन की उम्र के बजाय प्रदूषण के ऊपरी स्तर (जैसे बीएस-1 या बीएस-2 से पहले के वाहन) को स्क्रैप के लिए मानक बनाया जा सकता है।'

हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल यह चर्चा के दौर में है।

फिलहाल दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करने का नियम लागू है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के अनुसार, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं चल सकते। कोर्ट ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए यह आदेश दिया था।

अनुराग जैन ने कहा कि 'इसके लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने की एक विश्वसनीय प्रणाली की आवश्यकता होगी। इस पर उद्योगों से राय मांगी गई है। चूंकि यह पाया गया है कि हाल के दिनों में पीयूसी के सख्त नियमों की कमी के कारण कई वाहनों को आसानी से फिटनेस प्रमाण पत्र मिल जाता है।

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ धवन के अनुसार ऐसी चीजें पहले भी होती रही हैं। लेकिन नीति में बदलाव नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत अच्छा होगा। यह आम लोगों के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि स्क्रैप से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। आज तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। इसलिए पहले वाहन बनाने पर खर्च करना और फिर उसके स्क्रैप पर खर्च करना, यह समझदारी नहीं है। वैसे भी स्क्रैप के लिए वाहन की उम्र का फॉर्मूला सही नहीं है। सरकार को स्क्रैप से बचने के उपाय खोजने चाहिए।

सड़क एवं सुरक्षा विशेषज्ञ अनुराग कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि सबसे पहले एनजीटी, केंद्र और राज्य के लिए एक जैसे नियम बनाए जाने चाहिए, ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति खत्म हो। प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए एक राज्य में अलग नियम हैं और दूसरे राज्य में अलग नियम हैं। स्क्रैप पॉलिसी के मामले में भी यही स्थिति है। स्क्रैप कार की उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि कार के रखरखाव के हिसाब से किया जाना चाहिए।

खुशखबरी! दिल्ली मेट्रो में एक QR टिकट पर करें बार-बार ट्रैवल, 20 फीसदी तक मिलेगा डिस्काउंट

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट (एमजेक्यूआरटी) की शुरुआत की है। अब यात्रियों को बार-बार क्यूआर टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को दिल्ली सारथी (मोमेंटम 2.0) ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पीक आवर्स में 10% और ऑफ-पीक आवर्स में 20% की छूट मिलेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट (एमजेक्यूआरटी) को गुरुवार को लॉन्च कर दिया। दिल्ली मेट्रो का यह एक अत्याधुनिक तकनीक है, जिसे यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यात्रियों को रोज-रोज क्यूआर टिकट खरीदने की झंझट मिल जाएगी और एक ही क्यूआर टिकट पर बार-बार यात्रा कर सकेंगे।

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने आज मेट्रो भवन में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस नई सुविधा को लॉन्च किया। इसका इस्तेमाल 13 सितंबर, 2024 से किया जा सकता है। यह सुविधा डीएमआरसी के दिल्ली सारथी (मोमेंटम 2.0) ऐप पर उपलब्ध रहेगी। इसके इस्तेमाल के लिए मेट्रो के यात्रियों को डिस्काउंट भी मिलेगा। पीक आवर्स (सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे से रात 9 बजे) के दौरान 10% की छूट और ऑफ-पीक आवर्स के दौरान 20% की छूट भी मिलेगी।

कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं

सबसे पहले यूजर्स को दिल्ली सारथी (मोमेंटम 2.0) ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए पैसेंजर्स को सबसे पहले 150 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। इसे पैसेंजर्स आगे की यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखी गई है। पैसेंजर्स यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी आसानी से रिजार्ज कर सकते हैं। इसमें 50 रुपये के गुणक पर अधिकतम 3000 रुपये तक का रिचार्ज किया जा सकता है।

दो महीने बंद रहेगी NH-48 की सर्विस रोड, गुरुग्राम से महिपालपुर तक ट्रैफिक रहेगा प्रभावित

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। एनएच-48 पर द्वारिका लिंक रोड मर्जिंग प्वाइंट से महिपालपुर पेट्रोल पंप तक सर्विस रोड मरम्मत कार्य के चलते 60 दिन तक बंद रहेगी। इस दौरान गुरुग्राम से महिपालपुर तक यातायात प्रभावित रहेगा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं कि NH-48 की सर्विस रोड बंद रहने की स्थिति में किस मार्ग का इस्तेमाल करें।

दक्षिणी दिल्ली। एनएच-48 पर द्वारिका लिंक रोड मर्जिंग प्वाइंट से महिपालपुर पेट्रोल पंप तक सर्विस रोड मरम्मत कार्य के चलते दो महीने तक बंद रहेगी। एनएसजी आफिस से महिपालपुर पेट्रोल पंप तक सर्विस रोड की मिट्टी ढहने की कगार पर है। रोड की मरम्मत एनएचआई करेगी। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अगले 60 दिनों तक इस पर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।

इस कारण गुरुग्राम से महिपालपुर तक यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात विभाग ने बुधवार को एडवाइजरी जारी करते महिपालपुर, वसंत कुंज, आइजीआइ एयरपोर्ट, धौला कुआं, नई दिल्ली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है।

यात्री इन रास्तों का करें इस्तेमाल

आया नगर बॉर्डर के माध्यम से महरौली-गुरुग्राम रोड।

पुराना गुरुग्राम रोड-कापसहेड़ा-समालखा रोड।

गुरुग्राम- द्वारका एक्सप्रेस वे-यशोभूमि- द्वारका सेक्टर 23 क्रासिंग-जानकी चौक- द्वारका सेक्टर 8/9 क्रॉसिंग- टी प्वाइंट सेक्टर 7- गणपति चौक-द्वारका सेक्टर 7/9 क्रासिंग- सेक्टर 6/7 क्रॉसिंग- सेक्टर 1 क्रासिंग- पालम फ्लाईओवर के लिए दाईं ओर मुड़ें- धौला कुआं।

डाबरी- गुरुग्राम रोड - द्वारका फ्लाईओवर - द्वारका रोड - स्टेशन रोड - परेड रोड।

गुरुग्राम - द्वारका एक्सप्रेसवे - यशोभूमि- महिपालपुर - धौला कुआं।

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का इस्तेमाल करें

गुरुग्राम से आइजीआई एयरपोर्ट या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने के लिए द्वारा सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो लें।

दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को कार्यस्थल, एयरपोर्ट, अस्पताल या रेलवे स्टेशन जाने के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलें।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

राजधानी की सड़कों से गायब हो जाएगी ग्रामीण सेवा ऑटो ? दिल्ली सरकार कर रही विचार

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार सड़कों से ग्रामीण सेवा वाहन को हटाने पर विचार कर रही है। इसकी जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाया जाएगा। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ग्रामीण सेवा ऑटो को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना पर काम कर रही है। अभी राजधानी में करीब 3000 हजार वाहन चल रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ग्रामीण सेवा को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार ग्रामीण सेवा ऑटो को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी करके उन्हें नया बना देने की योजना बना रही है।

2010 में शुरू हुई थी ग्रामीण सेवा योजना

2010 में शुरू की गई ग्रामीण सेवा एक पैरा-ट्रांजिट योजना है, जिसमें छह यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले उच्च क्षमता वाले तिपहिया वाहनों को दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों, अनधिकृत, पुनर्वास कालोनियों और जेजे क्लस्टरों में चलने की अनुमति दी गई थी। एक अधिकारी ने कहा कि ये वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील की कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण साधन हैं।

दिल्ली में छह हजार पंजीकृत थे ग्रामीण सेवा ऑटो

हमें उनके संगठन के ज्ञापन मिले हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक वाहनों में उनके परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। एसोसिएशनों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं और उनसे सेवाओं में नई जान फूंकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

अधिकारियों के अनुसार लगभग 6,000 पंजीकृत ग्रामीण सेवा ऑटो थे। हालांकि उनमें से कई समय बीतने के साथ सड़कों से गायब हो गए हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लगभग 2,000 से 3,000 वाहन चल रहे हैं।

परिवार का रखना चाहती हैं खास ख्याल, महिलाएं 5 तरीकों की लें मदद, पूरी फैमिली की कर सकेंगी देखभाल

याया जाए. इससे फैमली के सभी मेंबर्स हैप्पी और हेल्दी फील करेंगे और आप उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं रहेंगी.

डाइट का रखें ध्यान: आजकल ज्यादातर लोग, खासकर बच्चे जंक फ़ूड को डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं. ऐसे में जरूरी है परिवार की महिलाएं अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर घर के बड़े और बच्चों की डाइट का ध्यान रखें. साथ ही जंक फ़ूड को अवॉइड करके परिवार के सभी सदस्यों को पोषक तत्वों से भरपूर चीजें सर्व करें. इससे घर के किसी सदस्य की सेहत अनहेल्दी डाइट की वजह से ख़राब नहीं होगी.

एक्सरसाइज पर करें फोकस: फैमिली के सभी मेंबर फिट एंड फाइन बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि घर के सभी सदस्यों को डेली एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित किया जाए. ऐसे में आप हर फैमली मेंबर को वॉकिंग, साइकलिंग, योग और स्पोर्ट एक्टिविटी जैसी चीजों को रुटीन में शामिल करने की सलाह दें. इस तरीके से घर के सभी सदस्य फिट एंड फाइन बने रहेंगे.

सेविंग को न करें नजरअंदाज: आपका परिवार हमेशा खुश रहे इसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है, इसलिए घर की महिलाओं के लिए जरूरी है कि वह हर महीने की इनकम से थोड़ी-थोड़ी सेविंग करती रहें. इसके साथ ही घर के मेम्बर्स को फिजूल खर्ची न करने की सलाह दें और खुद भी इस पर अमल करें. इस तरीके से कभी इमरजेंसी आ जाने पर आपको पैसों की टेंशन नहीं रहेगी.

सेफ्टी का रखें ख्याल: आजकल का माहौल काफी ख़राब है, ऐसे में खुद के साथ बच्चों और बड़ो की सेफ्टी का ख्याल भी जरूर रखें. इसके लिए बच्चों की अपब्रिंगिंग का भी ध्यान रखें और उनके स्कूल और दोस्तों से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करती रहें. इसके साथ ही घर से बाहर जाते समय सबकी सुरक्षा पुख्ता कर लें, जिससे फैमली में खुशियां और पॉजिटिविटी बरकरार रह सके।

प्रोटीन से भरपूर बाजरा देगा शरीर को कई फायदे, हार्ट भी रहेगा स्वस्थ

गेंहू-चावल की जगह आप बाजरे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, इस को सूपर फूड भी कहा जाता है। जहां चावल में लगभग 82 % कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वहीं गेंहू में 76% और बाजरे में 78% कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इसके अलावा बाजरे में कॉम्पलेक्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माने जाते हैं। इसका सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसके अलावा यह खून में चीनी की मात्रा बढ़ने से भी रोकता है। बाजरे का सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल और हार्ट हेल्दी रखने में मदद मिलती है। तो चलिए आपको बताते हैं इसे खाने से सेहत और क्या-क्या फायदे होते हैं...

नाश्ते में खाने से मिलेगा फायदा

एक्सपर्ट्स की मानें तो यदि बाजरे का सेवन सही समय पर किया जाए तो शरीर को ज्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। ब्रेकफास्ट के तौर पर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आप सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे और आपका पेट भरा हुआ रहेगा। इसके अलावा दोपहर के भोजन में गेंहू या फिर चावल की जगह आप इसका सेवन कर सकते हैं। रात में बाजरे का सेवन करने से पाचन में मदद मिलती है। इसमें फाइबर काफी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है जिससे आपको रात में काफी अच्छी नींद आती है।

अच्छी मात्रा में मौजूद होता है प्रोटीन

बाजरे में लगभग 8-12 ग्राम प्रोटीन, फॉक्सटेल बाजरे में 10-12 ग्राम प्रोटीन और रागी में करीबन 7-10 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। इसके अलावा बाजरे की अलग-अलग किस्म में भी प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा

में मौजूद होता है। गेंहू या चावल की जगह आप इसका सेवन कर सकते हैं।

मिनरल्स और विटामिन्स युक्त

बाजरा और रागी में बी1, बी2, बी3, बी5, बी6 और बी9 काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन्स एनर्जी बढ़ाने, पाचन और रेड ब्लड सेल्स कोशिकाएं बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा रागी में विटामिन-के, ए, कैल्शियम, सेलेनियम और आयरन काफी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट्स बी सामिल होते हैं जो सुपरऑक्साइज रेडिकल्स का असर कम करते हैं।

हार्ट को रखता है स्वस्थ

एक्सपर्ट्स की मानें तो बाजरे में मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह हार्ट को स्वस्थ रखने के साथ-साथ उसे धड़कने में भी मदद करता है। इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन, कार्डियोवेस्कुलर टिश्यू को बचाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला विटामिन-बी3 हार्ट डिजीज का खतरा कम करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में मदद करता है।

अकेलेपन से नहीं उबर पा रहीं? 5 टिप्स की मदद से खुद को रखें पॉजिटिव, डिप्रेशन एंजाइटी भी रहेंगे दूर

लोगों के बीच रहते हुए भी खुद में अकेलापन महसूस करना आपके मेंटल हेल्थ को काफी प्रभावित कर सकता है. खुद को अगर आप ऐसे हालात से बाहर निकालना चाहती हैं तो कुछ टिप्स की मदद लें.

अकेलापन, हालात नहीं, एक तरह की फीलिंग है जिसमें इंसान भीड़ में रहकर भी खुद को अलग थलग पाता है. यह आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और अगर आप इस इमोशन को सही तरीके से डील ना कर पाए तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की गिरफ्त में आसानी से आ सकते हैं. यही नहीं, अधिक दिनों तक अगर आप इस हालात में रहे तो ये आपके शारीरिक सेहत को भी प्रभावित करने लगता है. अगर आप भी इस तरह अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप सकारात्मक महसूस कर सकते हैं.

अकेलेपन को ऐसे करें दूर

क्लब या क्लास ज्वाइन करें

वेरीवेल माइंड के मुताबिक, अगर आप खुद को अलग थलग महसूस करें तो जरूरी है कि आप अपने लिए एक ऐसा ग्रुप ढूंढ लें जिसमें आपके जैसे लोग हों. इसके लिए आप अपने आसपास कोई क्लब या हॉबी क्लास ज्वाइन करें. इस तरह आप एक ग्रुप का हिस्सा बन पाएंगे और खुद को अकेलेपन से बाहर निकाल पाएंगी.

इन उपायों से दूर होगी घर की निगेटिव एनर्जी आगे देखें...

वॉलेंटियरिंग करें

अगर आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई रहेंगी तो आप बेहतर महसूस कर पाएंगी. इसके लिए आप उन जगहों पर वॉलेंटियरिंग कर सकते हैं जहां काम कर आप लोगों की मदद कर सकें और दूसरों की जिंदगी को आसान बना पाएं. यह भावना आपके अकेलेपन को दूर करने का काम कर सकती है.

ऑनलाइन सपोर्ट

आप सोशल मीडिया का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें और फीयर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग से बाहर निकालें. यहां आकर आप लोगों से जुड़ सकते हैं और बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं.

अपनों से मिलें जुलें

अगर आप बेहतर महसूस ना कर पा रही हैं तो अपने उन परिवार के सदस्यों, पुराने दोस्तों या टीचर आदि से मिलने का प्लान बनाएं जिनके साथ आप पॉजिटिव महसूस करती हैं. यकीन मानिए, आप ऐसे लोगों से मिलकर बेहतर महसूस करेंगे और आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा.

सेल्फ केयर

खुद के लिए वक्त निकालना शुरू करें. वॉक पर जाएं, रिलैक्स करें, भरपूर नींद लें, अपने पसंद की चीजों को बनाएं और खाएं. डॉक्टर से मिलें, चेकअप कराएं और जरूरी सप्लीमेंट का सेवन करें और खुद को व्यस्त रखें.

पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं मातृभाषा का महत्व

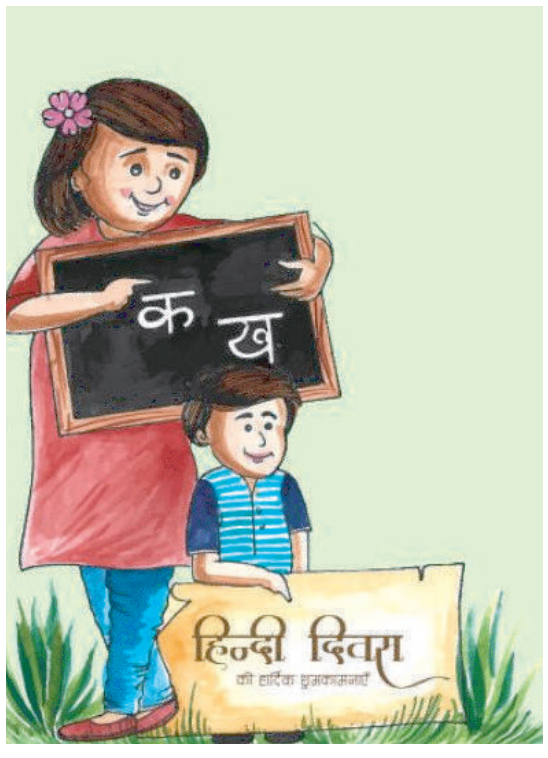

बदलते दौर में अंग्रेजी का चलन इतना बढ़ गया है कि लोग हिंदी भाषा की अहमियत ही भूलते जा रहे हैं। हिंदी दिवस का महत्व बताने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बदलती पीड़ी हिंदी का महत्व बिल्कुल भूलती जा रही है। ऐसे में बच्चों को अपनी मातृभाषा के पास रखना जरुरी है। बच्चों को हिंदी भाषा की अहमियत बतानी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि हिंदी का इतिहास कितना समृद्ध है। आज हिंदी दिवस के मौके पर आपको बताते हैं कि आप बच्चों को मातृभाषा के करीब कैसे रख सकते हैं....

रोजाना करें हिंदी का इस्तेमाल

बच्चे अपने आस-पास जो भी चीजें देखते हैं या सुनते हैं उसको बहुत ही जल्दी सीखते हैं ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि वह अपनी भाषा के करीब रहें तो रोजाना की रुटीन में हिंदी भाषा शामिल करें। इस तरह वह हिंदी को जान पाएंगे। हिंदी में आप उन्हें कविताएं, कहानियां, मुहावरें सुनाएं। इससे उनको भाषा भी समझ आएगी और इसके प्रति उनका सम्मान भी बढ़ेगा।

बच्चों को सिखाएं भाषा की अहमियत

व्यक्ति किसी भी चीज की कद्र तभी करता है अगर उसको उस चीज की अहमियत पता हो। ऐसे में जरुरी है कि आप बच्चों को मातृभाषा की अहमियत सिखाएं। पहले बच्चों को स्कूल में यह बताया जाता था लेकिन अब बदलते समय के साथ स्कूल में अंग्रेजी पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। ऐसे में जिंदगी की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं इसलिए जरुरी है कि उन्हें भाषा की अहमियत सिखाई जाए।

इतिहास के बारे में बताएं

बच्चों को आप हिंदी भाषा का इतिहास जरुर बताएं। उन्हें बताएं कि हिंदी भाषा में लिखे लेखकों के लेख पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। मातृभाषा में काम करने वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया में सम्मान की नजर के साथ देखा जाता है। इस तरह की बातें जानकर बच्चों के दिल में हिंदी भाषा के प्रति आत्म सम्मान बढ़ेगा।

स्पीच करवाएं तैयार

आप बच्चों को हिंदी दिवस पर एक स्पीच तैयार करवा सकते हैं। इससे बच्चों को हिंदी बोलनी भी आएगी और उनमें इसे लेकर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

दिल से लेकर दातों तक को मजबूत करती है ब्रॉकली, जानिए इसे खाने के अनेक फायदे...

ब्रोकली वैसे दिखने में तो गोभी जैसा नजर आता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। बता दें प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए प्रोटीन की पूर्ति के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही इसमें कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन ए, सी और कई दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें कई प्रकार के लवण भी पाए जाते हैं, जो शुगर लेवल को संतुलित बनाए रखने में मददगार हैं....

इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ब्रोकली

ब्रोकली में विटामिन सी प्रचूर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने और संक्रमण से बचाने में मददगार है।

दिल को रखती है स्वस्थ

इसमें पाए जाने वाले सेलेनियम और ग्लूकोसिनोलेट्स जैसे तत्व दिल को स्वस्थ रखने वाले प्रोटीन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए यह दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है।

लीवर को करता है मजबूत

ब्रोकली को डाइट में शामिल करने से लिवर क्षति का जोखिम कम होता है। साथ ही फैटी लिवर की समस्या में लाभ मिलता है। इसलिए लीवर को मजबूत बनाने के लिए ब्रोकली का सेवन करना चाहिए।

प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी लाभकारी

ब्रोकली में मौजूद प्रोटीन, आयरन, फोलेट और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जरूरी माने जाते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका सेवन जरूर करना चाहिए।

हड्डियों और दांतों की सेहत का रखती है ख्याल

इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो हड्डियों और दांतों के लिए बहुत लाभकारी है।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा : बरसात के दौरान सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान

डॉ. अंकुर शरण

सड़क सुरक्षा का महत्व हर समय बना रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, दृश्यता कम हो जाती है, और ड्राइविंग के दौरान छोटी-छोटी गलतियों का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम में से अधिकतर लोग किसी बीमारी के होने पर डॉक्टर से सलाह लेते हैं, लेकिन जब सड़क सुरक्षा की अनदेखी करते हैं, तो परिणामस्वरूप दुर्घटनाएँ होती हैं, जिससे बड़ी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि बारिश के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरती जाए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जो बारिश के मौसम में सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए पालन किए जाने चाहिए:

1. गति नियंत्रित रखें:

बारिश के दौरान सड़कें गीली और फिसलन भरी होती हैं, इसलिए गाड़ी की गति नियंत्रित रखना बेहद ज़रूरी है। अत्यधिक गति के कारण अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी फिसल सकती है और दुर्घटना हो सकती है।

2. ब्रेक का सही इस्तेमाल करें:

बारिश में अचानक ब्रेक लगाने से बचें, इससे गाड़ी फिसल सकती है। धीरे-धीरे ब्रेक लगाकर गाड़ी की गति कम करें और ब्रेकिंग दूरी को ध्यान में रखें।

3. विंडशील्ड वाइपर और लाइट्स का उपयोग:

बारिश के दौरान दृश्यता कम हो जाती है, इसलिए विंडशील्ड वाइपर को नियमित रूप से चलाएं और गाड़ी की हेडलाइट्स और टेललाइट्स चालू रखें ताकि सामने और पीछे से आने वाले वाहन आपको देख सकें।

4. टायर की जाँच करें:

गाड़ी के टायर का सही ग्रिप होना आवश्यक है। बारिश के मौसम में टायर की फिसलन बढ़ जाती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि टायर की सतह अच्छी स्थिति में हो और वायु दबाव सही हो।

5. सड़क की स्थिति का ध्यान रखें:

बारिश में सड़क पर पानी जमा हो सकता है जिससे जलभराव या ऱहाइड्रोप्लेनिंगऱ की स्थिति बन सकती है। ऐसी जगहों पर धीमी गति से गाड़ी चलाएं और जलभराव वाले हिस्सों से बचने की कोशिश करें।

6. अन्य वाहनों से उचित दूरी बनाए रखें:

गीली सड़कों पर ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा सामने चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाए रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय रहते ब्रेक लगा सकें।

7. ओवरटेक करने से बचें:

बारिश के दौरान ओवरटेक करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि दृश्यता कम होती है और सड़कों पर अचानक से फिसलन हो सकती है। जब तक अत्यधिक ज़रूरी न हो, ओवरटेक करने से बचें।

8. मोटरबाइक और साइकिल चालकों के लिए विशेष सतर्कता:

बाइक और साइकिल चालकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हेलमेट का उपयोग करें और गीली सड़कों पर धीमी गति से चलें। बाइक के टायरों और ब्रेक की जाँच करें।

9. साइड मिरर और इंडिकेटर का सही इस्तेमाल:

बारिश में गाड़ी मोड़ने या लेन बदलने से पहले इंडिकेटर का उपयोग करें और साइड मिरर की मदद से पीछे और बगल के वाहनों की स्थिति का पता लगाएं। अचानक मोड़ने से बचें।

10. विश्राम और मानसिक स्थिति:

बरसात के दौरान सड़क पर ध्यान भटकने की संभावना बढ़ जाती है। गाड़ी चलाते समय पूरी तरह सतर्क रहें और यदि आप थके हुए महसूस कर रहे हों तो गाड़ी न चलाएं। मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होना सड़क पर दुर्घटनाओं से बचाने में मदद करता है।

बारिश के मौसम में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना न केवल आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। छोटी-छोटी लापरवाहियों से बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। जिस प्रकार किसी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह ली जाती है, उसी प्रकार सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक है। सावधानीपूर्वक ड्राइविंग करना, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना, और सतर्क रहना ही बारिश के दौरान सुरक्षित यात्रा की कुंजी है।

roadsafetysquad@gmail.com

न्यायिक अधिकारी की बहाली न होने से SC नाराज, पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप पर हुआ था बर्खास्त

परिवहन विशेष

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला न्यायिक अधिकारी के साथ कथित अफेयर के लिए बर्खास्त किए गए न्यायिक अधिकारी को बहाल नहीं करने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अधिकारी की बर्खास्तगी को रद किया था। फिर भी हाई कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। शीर्ष अदालत ने कर्मचारी को 2 अप्रैल 2024 तक बहाल करने को कहा था।

नई दिल्ली। एक महिला न्यायिक अधिकारी के साथ कथित अफेयर के लिए बर्खास्त किए गए न्यायिक अधिकारी को बहाल नहीं करने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई है। शीर्ष अदालत ने 2022 में इस न्यायिक अधिकारी के बर्खास्तगी पत्र को रद कर दिया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि शीर्ष अदालत ने 20 अप्रैल, 2022 को पुरुष न्यायिक अधिकारी के 25 अक्टूबर, 2018 के बर्खास्तगी आदेश को रद कर दिया था और हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ को बर्खास्तगी के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 26 अक्टूबर, 2018 को हाई कोर्ट की उसी खंडपीठ ने अवैध संबंध के आरोप पर अविश्वास जताते हुए महिला न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा..

शीर्ष अदालत ने हालिया आदेश में कहा कि जब बर्खास्तगी आदेश रद (2022 में सुप्रीम कोर्ट ने) कर दिया गया है। साथ ही बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के हाई कोर्ट के फैसले को भी रद कर दिया गया है तो कर्मचारी को सेवा में वापस लिया जाना चाहिए।

फिर निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन न तो हाई कोर्ट ने और न ही राज्य ने इस पर कोई फैसला लिया और न ही बर्खास्तगी की तिथि से बकाये वेतन पर कोई आदेश जारी किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी उसके 20 अप्रैल, 2022 के फैसले की तिथि से दो अप्रैल, 2024 को जारी नए बर्खास्तगी आदेश तक पूर्ण वेतन के हकदार होंगे और अपीलकर्ता को सेवा में मानते हुए सभी लाभ भी दिए जाएंगे।

जहां तक 17 दिसंबर, 2009 को जारी पहले बर्खास्तगी आदेश से लेकर इस अदालत के बहाली आदेश तक की अवधि का सवाल है तो लगातार सेवा में मानते हुए अपीलकर्ता 50 प्रतिशत बकाया वेतन के हकदार होंगे और उसकी गणना कानून के तहत सभी लाभों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

पीठ ने न्यायिक अधिकारी को हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के 3 अगस्त, 2023 के प्रस्ताव एवं 2 अप्रैल, 2024 को जारी नए बर्खास्तगी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने की छूट भी दी।

रेजिडेंट डॉक्टरों से, दिल्ली सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर बातचीत की

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में प्रशिक्षण ले रहे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के रेजीडेंट डॉक्टरों से की मुलाकात I मुलाकात के दौरान डॉक्टरों से, अस्पताल में मिल रहे प्रशिक्षण, सरकारी सुविधाओं तथा अन्य इंतजाम के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रेजिडेंट डॉक्टरों को दिल्ली सरकार की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया I साथ ही साथ रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बेहद सजग है I रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल में मिल रहे प्रशिक्षण की तारीफ की I साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं बेहतर की हैं।

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में प्रशिक्षण ले रहे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के दर्जनों रेजिडेंट डॉक्टर से मुलाकात की मंत्री I सौरभ भारद्वाज ने सभी डॉक्टर्स से विस्तार के साथ बातचीत की और उन सभी से अस्पताल में मुहैया कराई जारी दिल्ली सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाओं के बारे में जाना, साथ ही साथ सभी डॉक्टरों से खासकर महिला डॉक्टर से अस्पताल में किसी प्रकार के शोषण या अन्य परेशानी के संबंध में भी बातचीत की I सभी रेजीडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल में बेहतर प्रशिक्षण मिलने की बात कही, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के शोषण से भी इनकार किया I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सभी रेजीडेंट डॉक्टरों को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सजग है और यदि उन्हें अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या उनका शोषण किया जाता है, तो वह सीधे तौर पर मंत्री सौरभ भारद्वाज से आकर मिल सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं I सभी रेजीडेंट डाक्टर मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस शालीन रवैया से खुश नजर आए तथा साथ ही साथ उन्होंने मंत्री सौरभ भारद्वाज का उनके प्रति चिंता व्यक्त करने के लिए आभार व्यक्त किया I

बातचीत के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर ने दिल्ली सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए मुहैया कराई जा रही सुविधाओं की तारीफ की I साथ ही साथ उन्होंने कहा की अस्पताल में प्रशिक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं, वह भी बहुत बेहतर है I अस्पताल में लिखित प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है I जहां एक तरफ अस्पताल में भी लिखित प्रशिक्षण के लिए क्लासरूम बना हुआ है,

मुलाकात के दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पताल में बने क्लासरूम जहां डॉक्टरों को लिखित प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका भी मुआयना किया I भारद्वाज ने मौके पर मौजूद अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि डॉक्टर के बैठने के लिए बेहतर कुर्सियों व टेबलों के इंतजाम किए जाएं I

मुलाकात के दौरान कुछ रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल में कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का भी अनुरोध किया I उन्होंने बताया कि अस्पताल में लगभग सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, परंतु कुछ जगहों पर अभी भी कैमरा लगवाने की आवश्यकता है तथा कुछ सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े हैं, उन्हें दुरुस्त करने की आवश्यकता है I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पताल प्रशासन को कहा कि जहां-जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं, उन जगहों पर भी जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और खराब पड़े सीसीटीवी को भी जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए।

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पताल प्रशासन को कहा, कि डॉक्टरों का जो ड्यूटी रूम है उस रूम में डॉक्टर के बैठने के लिए बेहतर कुर्सी और मेज की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ डॉक्टर के लिए स्वच्छ और ठंडे पानी हेतु वॉटर डिस्पेंसर की भी व्यवस्था की जाए।

मुलाकात के दौरान कुछ रेजिडेंट डॉक्टरों ने हॉस्टल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज से शिकायत की I डॉक्टर ने बताया कि हॉस्टल में खाने की क्वालिटी बेहतर नहीं है I कुछ पुरुष डॉक्टर ने हॉस्टल में शौचालय की खराब स्थिति की भी शिकायत की I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मौके पर ही मौजूद अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को इस संबंध में तुरंत व्यवस्था दुरुस्त कराने को कहा I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शौचालय की सफाई की व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए और साथ ही साथ हॉस्टल को बेहतर क्वालिटी का खाना मुहैया कराने के निर्देश जारी किए जाएं।

केजरीवाल की पांच गारंटियों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी : संजय सिंह

सुषमा रानी

बल्लभगढ़/ फरीदाबाद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उपस्थिति में तिगांव विधानसभा से आभाष चंदेला और बल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार ने नामांकन किया। इससे पूर्व, पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान जगह जगह आम आदमी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सांसद संजय सिंह ने रोड शो के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने तिगांव विधानसभा से आभाष चंदेला और वल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार को उम्मीदवार बनाया है। इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पांच गारंटियों पर चुनाव लड़ रही है। ये हम सभी हमारी माताओं बहनों, भाईयों और बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि 5 अक्टूबर को झाड़ू के निशान पर वोट पड़े। राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू जरूरी है। भाजपा के सत्ता का घमंड झाड़ू से दूर करने का वक्त आ गया है।

उन्होंने कहा इस बार ये झाड़ू के निशान को याद रखना है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में पांचों गारंटियों पर काम होगा। हरियाणा में अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने, फ्री शिक्षा, फ्री ईलाज, महिलाओं के लिए हर महीने एक हजार रुपये की सम्मान राशि और बेरोजगारों को सौ फीसदी रोजगार देने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि आपने भाजपा को मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। चौटाला की पार्टी को दिया। जेजेपी को मौका दिया। लेकिन, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की पांच गारंटियों को इस बार एक मौका दें और झाड़ू का बटन दबाने का काम करें। पिछले दस साल में बीजेपी ने महंगाई के नाम पर धोखा, बेरोजगारी के नाम पर धोखा, अग्निवीर के नाम पर नौजवानों के साथ धोखा करने का काम किया।

उन्होंने कहा कि पिछले दस साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को पीछे ले जाने का काम किया। दस साल के अंदर हरियाणा को बर्बाद करने का काम बीजेपी ने किया। इस बार बीजेपी के अहंकार को मिटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इस बार बीजेपी की एक भी सीट नहीं आना चाहिए। बीजेपी का सूपड़ा साफ होना चाहिए।

उन्होंने कहा बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का काम किया। मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का काम किया। मैं छह महीने जेल में रहकर आया। सतेंद्र जैन को जेल में डाल रखा है। अकेले अरविंद केजरीवाल जनता के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार जनता बीजेपी की तानाशाही का बदला लेने का काम करेगी। हरियाणा की जनता बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगी।

दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई जगहों पर लगा जाम; लोगों को हुई खूब परेशानी

परिवहन विशेष

राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कई जगहों पर बारिश हुई। इस कारण राजधानी के कई जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा जीटीके डिपो के पास जलजमाव के कारण मुकरबा चौक से आजादपुर चौक की ओर और इसके विपरीत दोनों कैरिजवे पर जीटीके रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है।

नई दिल्ली। दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव के कारण गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में यातायात जाम देखा गया। इंडिया गेट, जनपथ रोड, आरके पुरम, कालिंदीकुंज, गाजीपुर, इंदिरापुरम, लक्ष्मी नगर, द्वारका, कनॉट प्लेस, नोएडा, सफदरजंग, उत्तम नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश और रोहिणी सहित दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह हल्की बारिश हुई।

पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सड़क पर बड़े गड्ढे के कारण टी पॉइंट उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन से पंखा रोड की ओर ओल्ड पंखा रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "जीटीके डिपो के पास जलजमाव के कारण मुकरबा चौक से आजादपुर चौक की ओर और इसके विपरीत दोनों कैरिजवे पर जीटीके रोड पर यातायात प्रभावित है।"

गड्ढों और जलजमाव के कारण ट्रैफिक जाम

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि एमबी रोड पर खानपुर टी पॉइंट से महरौली की ओर और इसके विपरीत मार्ग में गड्ढों और जलजमाव के कारण यातायात प्रभावित है। इसी तरह, रोहतक रोड पर भी गड्ढों और जलभराव के कारण जाम लग गया। पुलिस ने कहा कि नजफगढ़ रोड पर नवादा से उत्तम नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई (बीएसईएस) द्वारा चल रहे काम के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित है।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने साल 2024-25 के लिए बिज़नेस बिज़नेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की घोषणा की

सुषमा रानी

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 सालों की उपलब्धि को देखते हुए अपने सभी स्कूलों में लगातार तीसरे साल 'बिज़नेस ब्लास्टर्स' प्रोग्राम को लॉंच किया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शिक्षा मंत्री आतिशी ने साल 2024-25 के लिए बिज़नेस बिज़नेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि, 2.45 लाख स्टूडेंट एंत्रप्रेन्योर, 40 करोड़ रुपये की सीड मनी और 40,000 से ज़्यादा स्टार्ट-एप आईडियाज के साथ एक बार फिर बिज़नेस-ब्लास्टर्स प्रोग्राम सुपरहिट साबित होगा।

उन्होंने कहा कि, एक तरफ़ पूरा शिक्षा तंत्र युवाओं को सिर्फ़ नौकरी की लंबी लाइनों में खड़ा होने के लिए तैयार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ़ केजरीवाल सरकार अपने स्कूली बच्चों को रोज़गार ढूँढने के बजाय रोज़गार देने वाला बना रही है।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, बिज़नेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हमारे युवा एंत्रप्रेन्योर आज अपने स्टार्ट-अप्स के दम पर न सिर्फ़ लाखों रुपये कमा रहे है बल्कि सैकड़ों लोगों को रोज़गार भी दे रहे है। उन्होंने कहा कि, यदि 12वीं की पढ़ाई कर निकले बच्चे युवाओं को रोज़गार दे सकते है तो यदि हर बच्चे को सही शिक्षा और मौक़ा दिया जाए तो देश भर में लाखों रोज़गार पैदा किया जा सकते है।

उन्होंने कहा कि, भारत बेरोज़गारी के मामले में विश्व के टॉप 3 देशों में शामिल है। देश में 42% युवा बेरोज़गार है। युवाओं के लिए 2030 तक 90 मिलियन नौकरियों की दरकार है। उन्होंने कहा कि, जब युवा नौकरी पाने की लाइन में लगने के बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे तभी देश से बेरोज़गारी का संकट ख़त्म होगा और बिज़नेस ब्लॉस्टर्स जैसे प्रोग्राम इस दिशा में महत्वपूर्ण है।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, आज के दौरान में भारत में बेरोज़गारी की समस्या सबसे बड़ी है। आज भारत के युवाओं की बेरोज़गारी 42% पर पहुँच गई है। बेरोज़गारी के आँकड़े में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आता है। मेकेंजी के 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत को यदि अपने सभी युवा जनसंख्या को नौकरी देनी है तो 2030 तक भारत में 90 मिलियन (9 करोड़) नॉन-एग्रीकल्चर नौकरियों की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि, इसी के तहत पिछले 3 साल से दिल्ली सरकार के स्कूलों में बिज़नेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत 11वीं-12वीं के बच्चों की सीड मनी दी जाती है। स्टूडेंट्स ख़ुद ग्रुप्स में अपने स्टार्ट-अप्स की शुरुआत करते है। और टॉप 150 स्टार्ट-अप्स को पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए खोला जाता है।

एक अन्य स्टूडेंट स्टार्ट-अप ए.के.लॉजिस्टिक्स जो अब एक रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स ने ट्रांसपोर्टेशन के अपने इस बिज़नेस में 50 लोगों को रोज़गार दे रहे है। कस्टमाइज्ड चॉकलेट बनाने वाले स्टूडेंट स्टार्ट-अप 'डार्क चॉकोबिट्स' 40 महिलाओं को रोज़गार दे रहा है। एक अन्य स्टूडेंट स्टार्ट-अप 'डिस्पोजल वाला' 20 लोगों को तो 'पढ़ाई-वढाई' स्टार्ट-अप 10 लोगों को रोज़गार दे रहा है।

उन्होंने कहा कि, मुझे आज ये घोषणा करते हुए ख़ुशी है कि, इस साल 2024-25 में भी बिज़नेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में की जा रही है। इस साल केजरीवाल सरकार अपने स्टूडेंट्स को 40 करोड़ रुपये की सीड मनी देगी। अबतक 2.45 लाख स्टूडेंट्स इस साल बिज़नेस ब्लास्टर्स में अपने 40,000 से ज़्यादा बिज़नेस आइडियाज़ के साथ भाग ले रहे है।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, मुझे पूरा भरोसा है कि, जिस तरह पिछले सालों में बिज़नेस ब्लास्टर्स के तहत हमारे स्टूडेंट्स ने न सिर्फ़ शानदार स्टार्ट-अप्स तैयार किए और लोगों को रोज़गार दिया, उसी तरह इस साल भी बिज़नेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत हमारे बच्चे नौकरी ढूँढने वाले नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई ख़त्म करने से पहले ही नौकरी देने वाले बनेंगे।

गाजियाबाद की अंबेडकर रोड पर चलेंगे ई-रिक्शा, विरोध के बाद बैकफुट पर आई पुलिस

परिवहन विशेष न्यूज

आंबेडकर रोड पर ई-रिक्शा संचालन पर प्रतिबंध करने के फैसले को गाजियाबाद यातायात पुलिस ने वापस ले लिया है। 12 सितंबर से अंबेडकर रोड पर भी ई-रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी लेकिन ई-रिक्शा चालकों प्रदर्शन के बाद फैसला टाला गया। इससे पहले हापुड़ रोड पर पुराना बस अड्डा से मसूरी फ्लाइओवर तक ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है।

गाजियाबाद। शहर में जाम की समस्या को करने के लिए पुलिस ने पहले एनएच- नौ, इसके बाद हापुड़ रोड पर पुराना बस अड्डा से मसूरी फ्लाइओवर तक ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है।

इसके बाद 12 सितंबर से अंबेडकर रोड पर भी ई-रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इसका विरोध हो गया। ई- रिक्शा चालकों के साथ ही सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष और व्यापारियों ने खुलकर विरोध किया तो पुलिस ने अंबेडकर रोड पर ई-रिक्शा को प्रतिबंधित करने का फैसला स्थगित कर दिया है।

पुलिस ने बुधवार को एक पत्र जारी कर बताया कि बुधवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने डीसीपी सिटी राजेश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, गाजियाबाद ई-रिक्शा एसोसिएशन के प्रतिनिधि, गाजियाबाद व्यापार मंडल के प्रतिनिधि पार्षदगण शामिल थे।

12 सितंबर से लगना था प्रतिबंध

प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि अंबेडकर रोड पर ई-रिक्शा के प्रतिबंध से सामान्यजनों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसका संज्ञान लेते हुए अंबेडकर रोड पर ई-रिक्शा चलाने पर 12 सितंबर से लागू होने वाले प्रतिबंध को स्थगित कर दिया गया है।

पुलिस आयुक्त कार्यालय पर ताला लगाने की चेतावनी

उधर, इस मामले में विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बयान जारी कर हापुड़ रोड पर ई-रिक्शा को प्रतिबंधित करने के विरोध में पुलिस आयुक्त कार्यालय पर ताला लगाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हापुड़ रोड से भी ई- रिक्शा के संचालन पर लगा प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो वे खुद ई- रिक्शा में सवार होकर हापुड़ रोड पर जाएंगे।

व्यवस्था बनाकर शहर में पुलिस कराए ई-रिक्शा संचालन

सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष जीतू शर्मा ने कहा कि शहर के अन्य स्थानों पर लगाए प्रतिबंध को भी पुलिस को वापस लेना चाहिए और व्यवस्था बनाकर शहर में ई-रिक्शा संचालन कराना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पहले दिन से विपक्ष शहर में ई-रिक्शा संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध कर रहा है। भाजपा नेता अपनी पीठ तभी थपथपाने के हकदार तभी होंगे जब वह पूर्व में ई-रिक्शा संचालन के बंद रास्तों को खुलवाएं। अभी पुलिस ने विपक्ष के विरोध से चलते अपने निर्णय को वापस लिया है।

गाजियाबाद के इस इलाके में पांच दिन से नहीं आ रहा पानी, 10 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित; विरोध में सड़क पर उतरे

इंदिरापुरम के न्याय खंड दो में पिछले पांच दिन से पानी की आपूर्ति प्रभावित है। मुख्य गंगाजल क्षतिग्रस्त है। जीडीए द्वारा लाइन की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है लेकिन अभी तक पेयजल लाइन ठीक नहीं हुई है। आज सुबह भी गंगाजल की आपूर्ति नहीं हुई तो लोगों को पानी खरीदना पड़ा। जीडीए के ओर से पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर नहीं भेजे गए।

परिवहन विशेष न्यूज

साहिबाबाद। न्याय खंड दो में पांच दिन से पानी नहीं मिलने पर बुधवार को लोगों का गुस्सा फूट गया। महिलाओं व पुरुषों ने काला पत्थर रोड स्थित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन और नारेबाजी की।

लोगों इंदिरापुरम हैंडओवर होने के बाद से जीडीए के सहायक अभियंता पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जबकि हैंडओवर के छह माह बाद तक पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जीडीए की है। इंदिरापुरम में सुबह और शाम के समय एक-एक घंटे जीडीए द्वारा गंगाजल की आपूर्ति की जाती है।

अधिकारी बोले- पेयजल लाइन में आ गया फाल्ट

गंगाजल में नलकूप का पानी भी मिलाया जाता है। न्याय खंड दो में पिछले पांच दिन से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। 10 हजार से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने जीडीए के अधिकारियों से शिकायत की तो उन्हें बताया गया कि पेयजल लाइन में फाल्ट आ गया।

लोग दो दिन तक फाल्ट ठीक होने का इंतजार करते रहे। इसके बाद अधिकारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। जब पांचवें दिन बुधवार को भी पानी नहीं आया तो न्याय खंड दो के सेंट्रल पार्क में लोग एकत्रित हो गए। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक रही। यहां से वह नारेबाजी करते हुए काला पत्थर रोड पर पहुंचे।

लोगों ने जीडीए कार्यालय पर किया प्रदर्शन

काला पत्थर रोड पर जाम लग गया। 100 से ज्यादा लोगों ने काला पत्थर रोड स्थित जीडीए के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि यहां कोई अधिकारी नहीं मिला। लोगों ने कहा कि पानी की जिम्मेदारी सहायक अभियंता पीयूष सिंह देख रहे हैं। प्रदर्शन में सरदार सिंह रावत, राजनी, चंपा, कल्पना रावत, सुरेंद्र कंडारी, सुरेंद्र उपाध्याय आदि मौजूद रहे। जीडीए के सहायक अभियंता पीयूष ने बताया कि समस्या को दूर करने के लिए काम चल रहा है।

खरीदना पड़ रहा है पानी

महिलाओं ने बताया कि बहुत कम संख्या में पानी के टैंकर आ रहे हैं। टैंकर आते ही पानी की मारामारी मच जाती है। उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। 20 लीटर पानी लेकर सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा है।

क्या बोले लोग ?

घर में पानी नहीं है। हम पानी के लिए तरस रहे हैं। जीडीए के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पानी खरीदना पड़ रहा है। - विमला, स्थानीय निवासी।

हैंडओवर होते ही जीडीए ने काम में लापरवाही करनी शुरू कर दी है। जबकि पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जीडीए की है। - साक्षी, स्थानीय निवासी।

हम चुप नहीं बैठेंगे। पांच दिन से पानी नहीं आया है। मजबूरी में हमें प्रदर्शन करने के लिए घर से निकलना पड़ा है। टैंकर नहीं भेजे जा रहे हैं। - उमा देवी, स्थानीय निवासी।

पांच दिन से पानी सर पर ढो रहे हैं। अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रतिदिन 200 रुपये का पानी खरीदना पड़ रहा है। - ममता, स्थानीय निवासी।

नोएडा ने लगाई ऊंची छलांग, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में स्थापित किया नया कीर्तिमान

नोएडा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तीन से दस लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा ने छठा स्थान प्राप्त किया है। यह नोएडा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह दूसरी बार है जब शहर ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। नोएडा के लोगों के लिए यह गर्व की बात है।

नोएडा। नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नोएडा ने रैंकिंग में ऊंची छलांग लगाई है। तीन से दस लाख की आबादी वाले शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण में पताका फहराने के बाद अब नोएडा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कीर्तिमान स्थापित किया है।

दूसरी बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला नोएडा ऊंची छलांग लगाकर छठे पायदान पर काबिज हुआ है। हालांकि प्रथम स्थान हासिल करने वाले फिरोजाबाद और दूसरा स्थान हासिल करने वाले झांसी से महज कुछ अंक पीछे रहा है।

शीर्ष पर पहुंच सकता है नोएडा

अब संभावना जताई जा रही है कि आगामी प्रतियोगिता में नोएडा अव्वल स्थान हासिल कर सकता है। सात सितंबर को वायु सर्वेक्षण 2024 का परिणाम जारी हुआ था। इसमें तीन केटेगिरी में शहरों ने प्रतिभाग किया था। इसमें तीन लाख से कम, तीन से दस लाख और दस लाख से अधिक शहर शामिल रहे। इस में तीन से दस लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा को छठा पायदान हासिल हुआ है।

पर्यावरण मंत्रालपय ने जारी की रिपोर्ट

मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट फारेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल इन शहरों की वायु गुणवत्ता को जांचा गया है।

जम्मू में हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण के जरिये 35:10 के फॉर्मूले पर जीत के प्रयास में बीजेपी

ओंकारेश्वर पांडेय

संजौली मस्जिद का विवाद तब उभरा जब कुछ हिंदू संगठनों ने इसके अवैध निर्माण का आरोप लगाया। उनका कहना था कि मस्जिद का निर्माण बिना प्रशासनिक मंजूरी के हुआ और इसे एक मंजिला से पांच मंजिला तक बढ़ा दिया गया।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जिस संजौली मस्जिद का निर्माण 1960 से पहले हुआ था और उसमें अवैध निर्माण भी 2010 में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समय शुरू हुआ, उसको लेकर विवाद आज अचानक इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे सांप्रदायिक नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था का मामला बताया है। लेकिन दरअसल यह मसला न तो सांप्रदायिक है, और न ही कानून व्यवस्था का, बल्कि यह सीधे सीधे राजनीतिक मामला है जिसे जम्मू-कश्मीर में इसी महीने हो रहे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

संजौली मस्जिद का विवाद तब उभरा जब कुछ हिंदू संगठनों ने इसके अवैध निर्माण का आरोप लगाया। उनका कहना था कि मस्जिद का निर्माण बिना प्रशासनिक मंजूरी के हुआ और इसे एक मंजिला से पांच मंजिला तक बढ़ा दिया गया। इस मुद्दे ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ध्यान भी आकर्षित किया, जहां ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसकी जांच की मांग की।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया

प्रशासन ने विवाद को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए। बुधवार को जब मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, तो शिमला में तनाव बढ़ गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई। जिला दंडाधिकारी ने संजौली क्षेत्र में सभी प्रकार के धार्मिक और भड़काऊ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया।

राजनीतिक दृष्टिकोण

अब इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बयान इस मामले को और भड़का रहे हैं। कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा का कहना है कि मस्जिद का निर्माण 1960 से पहले हुआ था, लेकिन अवैध विस्तार 2010 में हुआ। वहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे सांप्रदायिक मुद्दे के रूप में न देखने की अपील की है।

अदालत की प्रतिक्रिया

संजौली मस्जिद विवाद अदालत में है, जहां मस्जिद प्रबंधन से इसके विस्तार के बारे में सवाल किया गया है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि इस विस्तार से सामाजिक तनाव और सुरक्षा खतरे पैदा हो रहे हैं।

संजौली मस्जिद विवाद का चुनावी महत्व

संजौली मस्जिद विवाद का संबंध जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से भी जोड़ा जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक महादेव चौहान का मानना है कि इस समय इस विवाद को उठाने का एक अहम उद्देश्य हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मिल सकता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में हो रहे पहले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस विवाद को एक संवेदनशील मुद्दा बनाकर उभरा जा रहा है, जिसे बीजेपी अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव तीन चरणों में होंगे – 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। चुनावों के नतीजे 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ घोषित होंगे। 2018 में पीडीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार गिरने के बाद से यहाँ कोई निर्वाचित सरकार नहीं रही है।

चुनावों पर विवाद का असर

संजौली मस्जिद विवाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य में अनुच्छेद 370 हटने और इसे संघ शासित प्रदेश बनाये जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है, जिनमें से जिसमें जम्मू क्षेत्र में 6 नई सीटें जुड़ी हैं और अब वहां कुल 43 सीटें हो गयी हैं।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव और हिमाचल प्रदेश

पश्चिमी हिमालय पर्वत-श्रृंखला में बसे हिमाचल प्रदेश की 1170 कि.मी. लंबी सीमाओं में से उत्तर में जम्मू-कश्मीर, दक्षिण में हरियाणा, पश्चिम में पंजाब, पूर्व में तिब्बत (चीन), तथा दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड से लगती हैं। हिमाचल प्रदेश के चम्बा और काँगड़ा जिले तो सीधे जम्मू कश्मीर से लगते हैं, जबकि ऊना, चम्बा, सोलन, बिलासपुर, काँगड़ा जिले पंजाब से। सोलन, सिरमौर जिले हरियाणा से लगते हैं, तो किन्नौर, शिमला, सिरमौर उत्तराखण्ड से। वैसे हिमाचल का सिरमौर जिला उत्तर प्रदेश से भी लगता है। उधर किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले भी जम्मू कश्मीर के निकट चीन (तिब्बत) से लगते हैं।

जम्मू-कश्मीर में पहला चुनाव और संजौली मस्जिद विवाद

राजनीतिक विश्लेषक हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद को जम्मू-कश्मीर के चुनाव में लाभ लेने के दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके मुताबिक इस विवाद का एक अहम उद्देश्य हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण है, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में, बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र की दो सीटें जीती थीं। अब संजौली मस्जिद विवाद का उपयोग करके बीजेपी जम्मू क्षेत्र में हिंदू मतदाताओं का भरपूर समर्थन पाने का प्रयास कर रही है।

चुनावों पर संजौली मस्जिद विवाद का असर

यदि संजौली मस्जिद विवाद के चलते हिंदू मतदाता जम्मू क्षेत्र में एकजुट होते हैं, तो हिंदू बहुसंख्यक सीटों पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो सकती है। वैसे भी अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बीजेपी ने राष्ट्रवाद, सुरक्षा और धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर अपनी स्थिति मजबूत की है, जिसका लाभ उसे जम्मू में मिल सकता है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी राम माधव का दावा है कि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और अगली सरकार राष्ट्रवादियों की बनेगी। उन्होंने जम्मू रीजन में 35 सीटें और कश्मीर में 10 सीटें जीतने यानी 35:10 का फॉर्मूला पेश किया है।

अन्य पार्टियों की स्थिति

इस चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) ने राज्य में अनुच्छेद 370 की बहाली का मुद्दा उठाया कांग्रेस भी राज्य की बहाली की बात कर रही है, लेकिन वह अनुच्छेद 370 पर सीधा रुख अपनाने से बच रही है।

जम्मू के मुस्लिम बहुल जिले और बीजेपी की चुनौती

जम्मू के मुस्लिम बहुल पांच जिलों—डोडा, राजौरी, पुंछ, रामबन, और किश्तवाड़—में 16 सीटें हैं। इनमें से 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जिन पर बीजेपी को जीत का भरोसा है, लेकिन बाकी 11 सीटों पर मुकाबला मुश्किल है। जम्मू में 35 सीटें जीतने के बीजेपी के लक्ष्य में यही मुस्लिम बहुल जिले सबसे बड़ी चुनौती हैं, जहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा है। 2014 के विधानसभा चुनावों में जम्मू की 37 सीटों में से 25 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इनमें से उपरोक्त मुस्लिम बहुल जिलों में उसे महज 6 सीटें मिली थीं, वह भी मुस्लिम वोट बंटने से पहले। पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का मजबूत प्रदर्शन चुनौती पेश कर रहा है। इन दलों ने यहां चार से सात सीटें जीती थीं। तो अब जम्मू रीजन की 43 सीटों में बीजेपी को आरक्षित और हिंदू बहुल सीटों पर जीतने की उम्मीद है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत मुश्किल है।

कश्मीर घाटी में बीजेपी की स्थिति

उधर कश्मीर घाटी में बीजेपी ने कभी कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इस बार पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा के चुनाव में बीजेपी घाटी में निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है, जिनके जीतने की संभावना है। साथ ही गुलाम नबी आजाद और इंजीनियर राशिद जैसे नेताओं के साथ गठजोड़ कर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है।

हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण और बीजेपी की संभावनाएं

हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद जैसे मुद्दों को लेकर यदि बीजेपी जम्मू क्षेत्र में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करने में सफल रहती है, तो बीजेपी को 35 सीटों तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और 35:10 फॉर्मूले के तहत बीजेपी अगर जम्मू की 35 और कश्मीर की 10 सीटें जीतती है, तो यह राज्य के चुनावी परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकता है।

(लेखक एक प्रसिद्ध पत्रकार, राष्ट्रीय सहारा के पूर्व वरिष्ठ समूह संपादक, पूर्व संपादक-एएनआई, राजनीतिक टिप्पणीकार, रणनीतिकार, जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता और विचारक

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

ईवीएक्सपो ने शुरू किया ऑटो रिक्शा अभियान, ईवी कारोबार को फिर मिलेगा नया रंग

परिवहन विशेष न्यूज

हर साल की तरह ईवीएक्सपो ने दिसंबर 2024 में होने वाली 21वीं प्रदर्शनी के लिए ऑटो रिक्शा अभियान के साथ अपना प्रचार शुरू कर दिया है, ताकि निर्माताओं के साथ-साथ आगंतुकों को एक ही छत के नीचे बी2बी और बी2सी बढ़ाने का मौका मिले। इसके तहत ईवीएक्सपो ऑटो रिक्शा पर पोस्टर लगाकर लोगों को दिसंबर 2024 में प्रगति मैदान में होने वाली प्रदर्शनी में आने का निमंत्रण दे रहा है। इस अभियान की पहली शुरुआत दिल्ली भर में 200 ऑटो में पोस्टर लगाकर की गई है।

इस प्रदर्शनी के लिए प्रदर्शित पोस्टर में आपको ईवीएक्सपो का आयोजन ऑल्टियस ऑटो सोल्यूशन्स, टाइटल पार्टनर खालसा ईवी, को-पावर्ड ऑलिव, एसोसिएट पार्टनर सीवाई गोल्ड इंटरनेशनल, आइकेट और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित और साथ ही ईवी ड्राइव द फ्यूचर मीडिया पार्टनर के रूप में दिखाई देंगे।

20, 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में आने के लिए तैयार हो जाइए।

गाजियाबाद के अंबेडकर रोड पर ई-रिक्शा संचालन पर पाबंदी का फैसला पुलिस ने लिया वापस

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के अंबेडकर रोड पर ई-रिक्शा चलाने पर लगी रोक को पुलिस ने हटा लिया है। ई-रिक्शा संचालकों पर लगाई गई रोक को लेकर भाजपा, सपा और कांग्रेस के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ई-रिक्शा संचालकों पर लगाई गई रोक को लेकर गाजियाबाद में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अंबेडकर रोड पर पुराना बस अड्डा से लेकर चौधरी मोड़ तक ई-रिक्शा संचालकों पर रोक लगाई गई थी। यह आदेश गुरुवार, 12 सितंबर से लागू होना था। ई-रिक्शा संचालन पर लगी रोक हटने के बाद व्यापारियों और ई-रिक्शा चालकों ने राहत की सांस ली है।

गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाए रखने तथा जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुराना बस अड्डा से मालीवाड़ा चौक, कालकागढ़ी चौक होते हुए चौधरी मोड तक अंबेडकर रोड पर 12 सितंबर 2024 से ई-रिक्शा के संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया था। एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष, गाजियाबाद ई-रिक्शा एसोसिएशन के प्रतिनिधि, गाजियाबाद व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, पार्षद आदि शामिल थे। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि

इस प्रतिबंध के कारण आम जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ेगा तथा व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित होगा। मामले का संज्ञान लेते हुए जनहित में 12 सितंबर से लागू प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।र - राजेश कुमार, डीसीपी सिटी

अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) द्वारा जारी यातायात एडवाइजरी में कहा गया कि पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए ई-रिक्शा चालकों को सूचित किया जाता है कि 12 सितंबर से प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अंबेडकर रोड (पुराना बस अड्डा से मालीवाड़ा, कालका गढ़ी चौक होते हुए चौधरी मोड तक) पर ई-रिक्शा का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यातायात पुलिस ने इस निर्णय को वापस ले लिया है।

ई-रिक्शा संचालन को लेकर मेरठ पुलिस की नई योजना

परिवहन विशेष न्यूज

मेरठ में हजारों वैध-अवैध ई-रिक्शाओं से शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। पूरे दिन शहर में जाम के हालात बने रहते हैं। ई-रिक्शा चालकों की मनमानी से शहर के लोग कराह उठे हैं। इन हालातों से निपटने को मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने डीएम दीपक मीणा व एसएसपी को इसका हल निकालने को कहा था। इसके बाद यातायात पुलिस ने शहर में ई-रिक्शा संचालन की कार्ययोजना तैयार की है।

शहर को चार जोन रूट में बांटा गया है। रूट न. एक के लिए लाल रंग, रूट न. दो के लिए नीला, रूट न. तीन के लिए पीला व रूट न. चार के लिए हरा रंग निर्धारित किया गया है। हर ई-रिक्शा पर जोन रूट का एक स्टीकर व नंबर भी चस्पा करने की योजना है। इसका डिजाइन तैयार कर लिया गया है।

कार्ययोजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए डीएम-एसएसपी को भेजा गया है। इस पर विचार मंथन चल रहा है। मेरठ में ई-रिक्शा कोशिश है, जिन जोन में ई-रिक्शा का संचालन हो वह उसी कलर की हो और उस पर पंजीकरण स्टीकर लगा हो। यातायात पुलिस ने उम्मीद जताई कि योजना को अंतिम रूप एक-दो दिन में दे दिया जाएगा। इसके बाद यातायात पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देकर प्रभावी रूप से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

ई-रिक्शा को लेकर तैयार योजना पर विचार मंथन चल रहा है। इसमें जोन के लिहाज से निर्धारित कलर का स्टीकर, नंबर चस्पा करने की योजना है। जिन जोन में ई-रिक्शा चल रही है, उसका कलर भी उसी तरह का हो, ऐसे भी प्रस्ताव आए है। इन पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही स्वीकृति मिलते ही योजना को शहर में लागू कर ई-रिक्शाओं का पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। यातायात कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। - राघवेंद्र मिश्र, एसपी यातायात

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना को मिली मंजूरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगारों का होगा सृजन

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट योजना' के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। सरकार की यह पहल पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करेगी, साथ-साथ यह टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिहाज से भी अहम है। यह योजना अपने पीएमपी के साथ ईवी क्षेत्र और संबंधित आपूर्ति चेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। इसके अलावा यह योजना मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करेगी। विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के माध्यम से भी रोजगारों का सृजन होगा।

इस योजना में ई-एम्बुलेंस को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह केंद्र सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत मरीजों के आरामदायक परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-एम्बुलेंस के प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

यह योजना 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों को सहायता प्रदान करेगी। एमएचआई योजना के

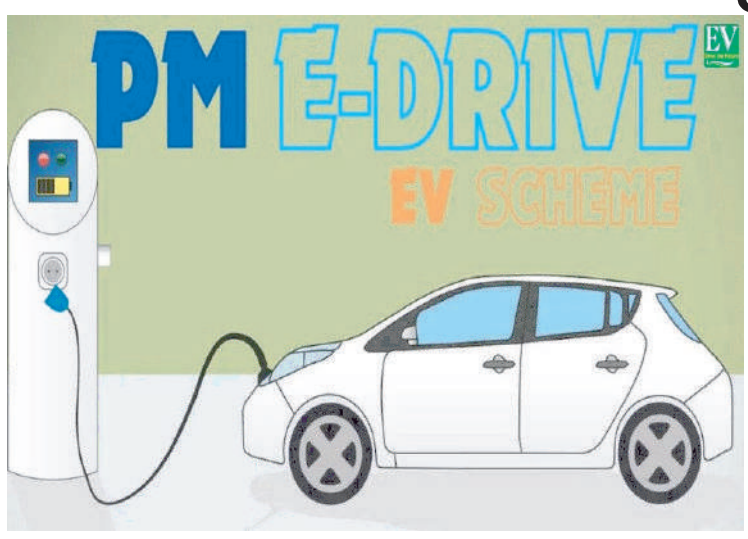

तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर पेश किया जा रहा है। ईवी की खरीद के समय, योजना के पोर्टल पर खरीदार के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर जारी होगा। ई-वाउचर डाउनलोड करने के लिए एक लिंक खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस ई-वाउचर पर खरीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए डीलर को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, ई-वाउचर पर डीलर द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हस्ताक्षर युक्त ई-वाउचर खरीदार और डीलर को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। योजना के तहत मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा करने के उद्देश्य से ओईएम के लिए हस्ताक्षरित ई-वाउचर आवश्यक होगा।

राज्य परिवहन निगमों (एसटीयू)/सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में मांग एकत्रीकरण का काम सीईएसएल द्वारा किया जाएगा। राज्यों के परामर्श से इंटरसिटी और अंतरराज्यीय ई-बसों को भी समर्थन दिया जाएगा। शहरों एवं राज्यों को बसें आवंटित करते समय, पहली वरीयता उन शहरों/ राज्यों को बसों को दी जाएगी, जिन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) वाहन स्क्रैपिंग योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से पुरानी एसटीयू बसों को स्क्रैप करने के बाद खरीदा जा रहा है।

देखा गया है कि ट्रकों से वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा होता है। पीएम ई-ड्राइव से देश में ई-ट्रकों के चलन को बढ़ावा मिलेगा। ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिनके पास मोर्थ द्वारा अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों (आरवीएसएफ) से स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र होगा।

यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर ईवी खरीदारों की चिंता को दूर करती है। ये ईवीपीसीएस बड़े स्तर पर ईवी की पैठ वाले चयनित शहरों और चयनित राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। इस योजना में ई-4 डब्ल्यू के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और ई-2 डब्ल्यू/3 डब्ल्यू के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है। ईवी पीसीएस के लिए परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये होगा।

इसके अतिरिक्त देश में ईवी इकोसिस्टम में बढ़ोतरी को देखते हुए, हरित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए एमएचआई की परीक्षण एजेंसियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। एमएचआई के तत्वावधान में 780 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन को मंजूरी दी गई है।

जयपुर के हर इलाके में अलग-अलग रंग के चलेंगे ई-रिक्शा

PM E-Drive Scheme के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर पहले साल 5000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी दूसरे साल 2500 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की खरीदारी पर पहले साल में 50000 रुपए तक की तो दूसरे साल में 25000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। दो साल में अधिकतम 25 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी।

नई दिल्ली। अगर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदना सोच रहे हैं तो अगले एक साल में खरीदना फायदेमंद रहेगा। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इनहासमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत दोपहिया वाहनों की खरीदारी पर अगले एक साल तक सरकार 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी, तो दूसरे साल यह सब्सिडी घटकर पांच हजार हो जाएगी।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम इलेक्ट्रिक कार नहीं शामिल

पीएम ई-ड्राइव स्कीम दो साल के लिए लाई गई है, जिसे गत बुधवार को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम आगामी एक अक्टूबर से लागू हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के प्रोत्साहन के लिए फिलहाल चल रही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) की अवधि आगामी 30 सितंबर को समाप्त होने जा रही है। पीएम ई-ड्राइव में इलेक्ट्रिक कार को शामिल नहीं किया गया है।

इलेक्ट्रिक कार पर लगता है पांच प्रतिशत जीएसटी

भारी उद्योग मंत्री एच.डी.कुमारस्वामी ने बताया कि पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार पर सिर्फ पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि अन्य कारों पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 20 प्रतिशत तक सेस लगते हैं। कुल मिलाकर गैर इलेक्ट्रिक बड़ी व मिड साइज कार पर 40 प्रतिशत तक का टैक्स लगता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक कार पर अलग से सब्सिडी नहीं दी जा रही है।

इतनी मिलेगी सब्सिडी

भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन अमूमन दो किलोवाट क्षमता वाले होते हैं। सरकार पीएम ई-ड्राइव के तहत पहले साल में 5000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी देगी, तो दूसरे साल में सब्सिडी की राशि घटकर 2500 रुपए प्रति किलोवाट की हो जाएगी। दो साल में अधिकतम 25 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की खरीदारी पर पहले साल में 50,000 रुपए तक की तो दूसरे साल में 25,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।

इस तरह करवाना होगा वेरिफिकेशन

मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी पर सब्सिडी लेने के लिए खरीदार को आधार के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। डीलर के पास जाने पर आधार से उनका वेरिफिकेशन होगा और खरीदार के मोबाइल नंबर पर ई-वाउचर जेनरेट करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। उस ई-वाउचर पर खरीदार और डीलर दोनों साइन करेंगे और उसे पीएम E-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और सब्सिडी डीलर के खाते में आ जाएगी। इस प्रक्रिया में खरीदार को सिर्फ अपने आधार से अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा। इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक एंबुलेंस के लिए भी सब्सिडी का प्रविधान किया गया है, लेकिन इस संबंध में ट्रांसपोर्ट विभाग और स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत चर्चा के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी।

एमजी विंडसर ईवी तीन वेरिएंट में हुई लॉन्च, जानिए इन तीनों के फीचर में क्या है अंतर

परिवहन विशेष न्यूज

MG Windsor EV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। इसे तीन वेरिएंट में पेश किया गया है जो एक्साइट एक्सक्लूसिव और एसेंस है। एमजी की तरफ से हाई-स्पेक वेरिएंट की कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है। विंडसर की बुकिंग 3 अक्टूबर से शुरू होगी और डिलीवरी 12 अक्टूबर से की जाएगी। आइए जानते हैं कि एक्साइट एक्सक्लूसिव और एसेंस में क्या फीचर्स दिए गए हैं।

नई दिल्ली। MG मोटर ने भारतीय बाजार में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल Windsor को लॉन्च किया है। इस मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। कंपनी ने इसे हर किलोमीटर पर 3.5 रुपये की अनूठी पे-एज़-यू-ड्राइव बैटरी रेंटल के साथ लेकर आई है। वहीं, इसपर अनलिमिटेड बैटरी वारंटी दे रही है। इसे तीन वेरिएंट में लाया गया है, जो एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस है। आइए जानते हैं कि तीनों वेरिएंट में फीचर के हिसाब से कितना अंतर है।

MG Windsor EV: एक्साइट वेरिएंट
एलईडी कॉर्नरिंग लाइट
इल्यूमिनेटेड फ्रंट लोगो
एलईडी लगेज लैंप
3.3kW पोर्टेबल चार्जिंग केबल
व्हील कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील
10.1-इंच टचस्क्रीन
7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
हिल डिसेंट कंट्रोल
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (हाईलाइन)
छह एयरबैग
ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल
ऑटो हेडलैंप
रिक्लाइनिंग रियर सीट
ग्लास एंटीना
छह स्पीकर
रियर एसी वेंट
एलईडी टेल लैंप
डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप
स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल
फ्रंट आर्मरेस्ट
एलईडी फ्रंट रीडिंग लाइट
फ्रंट और रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट
फैब्रिक सीट
फ्लश डोर हैंडल
60:40 रियर सीट स्प्लिट
वायरलेस Apple कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो
रेन-सेंसिंग वाइपर
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
3.3kW AC होम चार्जिंग बॉक्स
फ्रंट, रियर डिस्क ब्रेक
ड्राइवर की सीट मैनुअल हाइट एडजस्ट
ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
क्रूज कंट्रोल
हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट
क्रोम विंडो बेल्टलाइन
मल्टी-लैंग्वेज वॉयस कमांड
लेदरेट सीटें
रियरव्यू मॉनिटर
8.8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
MG ऐप स्टोर
स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल
LED रियर रीडिंग लाइट
18-इंच डायमंड कट एलॉय
लेदरेट स्टीयरिंग व्हील
15.6-इंच टचस्क्रीन
वाई-फाई कनेक्टिविटी
वायरलेस चार्जर
कप होल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट
डिजिटल की
360-डिग्री कैमरा
वैलेट मोड
OTA अपडेट
लेदरेट डैशबोर्ड
ऑटो-डिमिंग IRVM
पावर फोल्डिंग ORVM
TPMS
रिमोट कार लॉक/अनलॉक
जियोफाइबर
MG Windsor EV: एसेंस वैरिएंट
7.4kW AC फास्ट चार्जर
PM2.5 फ़िल्टर
वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें
एम्बिएंट लाइटिंग
ग्लास रूफ
इनफिनिटी 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

MG Windsor EV: डिजाइन

MG विंडसर EV में रीबैज्ड वर्शन, विंडसर एयरो ग्लाइड डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करती है। इसमें वर्टिकल स्टैक्ड हेडलैम्प, एक इल्यूमिनेटेड MG लोगो, शॉर्ट हुड के साथ बड़ी विंडस्क्रीन दी गई है। इसके साथ ही बड़ी लाइटबार 18-इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील और पीछे की तरफ फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल दिया गया है।

MG Windsor EV: बैटरी

विंडसर में IP67-रेटेड 38 kWh लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी दी गई है। यह बैटरी 134 bhp की पावर और 220 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। कंपनी दावा कर रही है कि उनकी यह गाड़ी 331 किलोमीटर तक का रेंज देगी। विंडसर को DC फ़ास्ट चार्जिंग से चार्ज होने में 55 मिनट का समय लगता है।

MG Windsor EV: इस दिन से होगी बुकिंग

डिजिटल साक्षरता क्या है और शिक्षा में इसकी भूमिका क्या है?

विजय गर्ग

ऐप्स और अपडेट के निरंतर विकास को देखते हुए, यह एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है? डिजिटल युग में, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में प्रौद्योगिकी का सामना करता है, जिसका अर्थ है कि डिजिटल उपकरणों में महारत हासिल करना अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। दुनिया भर के देशों में डिजिटल साक्षरता का स्तर अलग-अलग है, कम आय वाले देशों में साक्षरता सबसे कम है। मध्यम और उच्च आय वाले देशों के बीच असमानताएं भी महत्वपूर्ण हैं।

डिजिटल साक्षरता डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से जानकारी तक पहुंचने, प्रबंधन करने, समझने, एकीकृत करने, संचार करने, मूल्यांकन करने और उत्पादन करने की व्यापक क्षमता है। यह दक्षता शैक्षणिक सफलता, भविष्य की करियर संभावनाओं और आज के तकनीकी रूप से संचालित समाज में भागीदारी के लिए आवश्यक है। यहां कुछ डिजिटल साक्षरता कौशल दिए गए हैं जो आज की दुनिया में आवश्यक हैं: आलोचनात्मक सोच: डिजिटल युग में विभिन्न प्रारूपों में बड़ी मात्रा में जानकारी को छानने में एक समझदार मानसिकता के साथ जानकारी की खोज, मूल्यांकन, आवेदन और उत्पादन शामिल है। संचार कौशल: आभासी वातावरण में प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। इसमें विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, प्रासंगिक प्रश्न पूछना, सम्मान बनाए रखना और ऑनलाइन और ऑफलाइन विश्वास बनाना शामिल है। व्यावहारिक कौशल: नैतिक और स्थायी रूप से जानकारी तक पहुंचने, प्रबंधन, हेरफेर करने और बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अद्यतन ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐप्स और अपडेट के निरंतर विकास को देखते हुए, यह एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है? डिजिटल युग में, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में प्रौद्योगिकी का सामना करता है, जिसका अर्थ है कि डिजिटल उपकरणों में महारत हासिल करना अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। दुनिया भर के देशों में डिजिटल साक्षरता का स्तर अलग-अलग है, कम आय वाले देशों में साक्षरता सबसे कम है। मध्यम और उच्च आय वाले देशों के बीच असमानताएं भी महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के एक अध्ययन में पाया गया कि चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, क्रमशः केवल 1.6% और 2.4% वयस्कों ने कभी किसी फ़ोल्डर की प्रतिलिपि बनाई या उसे स्थानांतरित किया है। स्प्रेडशीट में बुनियादी फ़ार्मुलों का उपयोग करने जैसे कौशल भी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में काफी कम हैं। अमेरिका जैसे अधिक विकसित देशों में, अमेरिकियों के पास अलग-अलग डिग्री का डिजिटल ज्ञान है। जबकि एक महत्वपूर्ण हिस्से ने फ़िशिंग घोटाले जैसी बुनियादी डिजिटल अवधारणाओं की समझ का प्रदर्शन किया, कई लोग अधिक उन्नत विषयों के साथ संघर्ष करते रहे। उदाहरण के लिए, केवल 28% लोग दो-कारक प्रमाणीकरण की पहचान कर सकते हैं, और केवल 24% लोग ₹निजी ब्राउज़िंग₹ मोड की सीमाओं को समझते हैं, जैसा कि 2019 प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन द्वारा प्रकाशित किया गया है। डिजिटल साक्षरता में यह असमानता निरंतर शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है, खासकर जब प्रौद्योगिकी तेजी से दैनिक जीवन में एकीकृत होती जा रही है। दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता की कमी स्पष्ट होने के बावजूद, विभिन्न अनुपातों में, देशों में डिजिटल कौशल की मांग को अभी भी पूरा करने की आवश्यकता है। यूएनआईडीओ और विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्टों के आधार पर, जबकि कई अफ्रीकी देशों में बुनियादी डिजिटल कौशल की बढ़ती मांग देखी जा रही है, कई यूरोपीय देश और अमेरिका अधिक उन्नत डिजिटल निपुणता की मांग कर रहे हैं। 2018 और 2021 के बीच अमेरिका में डिजिटल जॉब पोस्टिंग में 24% की वृद्धि हुई, डेटा इंजीनियरों के लिए लिस्टिंग में 116% की वृद्धि हुई, उन्नत डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन और डिजिटल बिजनेस कौशल में दक्षता की मांग की गई। दूरस्थ कार्य के बढ़ने से डिजिटल कौशल और ऑनलाइन संचार का महत्व भी बढ़ गया है। पेशेवर सेटिंग्स में डिजिटल शिष्टाचार और ऑनलाइन मानदंडों और व्यवहारों को समझना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, उभरती दुनिया में निपुण बने रहने के लिए ऑनलाइन जानकारी को समझने और उसका उपयोग करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। जबकि डिजिटल साक्षरता वैश्विक आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करती है, यह ऑनलाइन खतरों से भी रक्षा करती हैसाइबरबुलिंग और घोटाले, सुरक्षित डिजिटल इंटरैक्शन प्रदान करते हैं। शिक्षा में डिजिटल साक्षरता की क्या भूमिका है? शैक्षणिक संस्थानों को कोविड-19 महामारी के दौरान एक आदर्श बदलाव का सामना करना पड़ा, जिसमें तेजी से ऑनलाइन शिक्षण की ओर परिवर्तन हुआ। हाल के वर्षों में डिजिटल लर्निंग और शिक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि और परिवर्तन देखा गया है, जिसमें हाइब्रिड लर्निंग केंद्र स्तर पर है। अनुमानों से संकेत मिलता है कि वैश्विक ई-लर्निंग बाजार 2022 तक 243 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। यह वृद्धि अकादमिक सफलता और बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए डिजिटल साक्षरता के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करती है, खासकर उच्च शिक्षा में। शिक्षा में ऑनलाइन पोर्टल से लेकर उन्नत अनुसंधान डेटाबेस तक डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीखने के परिणामों को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, 81% अमेरिकी कॉलेज छात्रों का कहना है कि डिजिटल शिक्षण तकनीकों ने उन्हें अपने ग्रेड बढ़ाने में मदद की, जैसा कि 2016 में स्टेटिस्टा द्वारा प्रकाशित किया गया था। विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य की करियर संभावनाओं को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही डिजिटल कौशल वाले और रचनात्मकता, समस्या-समाधान, सहयोग और आलोचनात्मक सोच जैसे सॉफ्ट कौशल का समर्थन करने वाले छात्रों को स्नातक होने के बाद बेहतर और उच्च-भुगतान वाली नौकरियां मिलने की संभावना है। अच्छी तरह

से विकसित डिजिटल कौशल के साथ, स्नातक भी उद्यमिता में छलांग लगाने और आगे बढ़ने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल साक्षरता सिखाना आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करें: विश्वविद्यालयों को छात्रों को डिजिटल सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, डेटा गोपनीयता को समझना और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक होना सिखाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकें। छात्रों को अपने काम में कई स्रोतों को खोजने, आलोचना करने, आत्मसात करने और संदर्भित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए ई-पाठ्यपुस्तकें और ऑनलाइन डेटाबेस जैसे संसाधन प्रदान करने से महत्वपूर्ण सोच कौशल बनाने में मदद मिलेगी। पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी को शामिल करना: शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने पाठ्यक्रम में डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों को सहजता से एकीकृत करें, सीखने के अनुभवों को बढ़ाएं और छात्रों को नवीनतम तकनीकों से परिचित कराएं। संस्थान छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में वीडियो, एनिमेशन, पॉडकास्ट या डिजिटल पत्रिकाएँ बनाने के लिए कह सकते हैं। प्रौद्योगिकी का नैतिक उपयोग: एआई और बड़े डेटा में तेजी से प्रगति के साथ, छात्रों के लिए चैटजीपीटी और मिडजर्नी जैसे कई उपकरण उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालयों को छात्रों को इन डिजिटल नवाचारों के नैतिक विचारों, संभावित पूर्वाग्रहों और सामाजिक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना चाहिए और उनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे करना चाहिए। सहयोग और समस्या-समाधान के अवसर प्रदान करें: डिजिटल सहयोग अनुभव प्रदान करें। आभासी समूह कार्य छात्रों को डिजिटल साक्षरता कौशल विकसित करने, विविध सहकर्मी अनुभवों से लाभ उठाने और डिजिटल संचार उपकरणों की बेहतर समझ में मदद करता है। आभासी वातावरण में एक साथ संवाद करने और काम करने के तरीके को समझने के लिए छात्र वर्चुअल मीटिंग, साझा क्लाउड दस्तावेज़ और फिगमा जैसे अन्य डिजिटल सहयोगी टूल के माध्यम से अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। शिक्षा में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ संसाधन सीमाएँ: कई शैक्षणिक संस्थानों में, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, उपकरणों और संसाधनों की कमी है। अपर्याप्त कंप्यूटर लैब, पुराना सॉफ़्टवेयर और हाई-स्पीड इंटरनेट तक सीमित पहुंच समस्या के प्राथमिक स्रोत हैं। प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास: सही उपकरणों के साथ भी, शिक्षकों को डिजिटल साक्षरता सिखाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक नवीनतम डिजिटल उपकरणों और प्रथाओं से अपडेट हैं, निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता है। परिवर्तन का विरोध: शिक्षक और छात्र दोनों कक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं। यह प्रतिरोध डिजिटल साक्षरता, प्रौद्योगिकी के डर या पारंपरिक शिक्षण विधियों की प्राथमिकता के बारे में गलत धारणाओं से उत्पन्न हो सकता है। विकसित हो रहा डिजिटल परिदृश्य: डिजिटल दुनिया लगातार बदलती रहती है, नए उपकरण, प्लेटफ़ॉर्म और प्रौद्योगिकियाँ नियमित रूप से उभरती रहती हैं। इन परिवर्तनों को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम प्रासंगिक बना रहे, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ संयुक्त पहल स्कूलों, सरकारी एजेंसियों और गैर-लाभकारी संगठनों के बीच गठजोड़ बनाकर संसाधनों को एकत्रित किया जा सकता है, विशेषज्ञता साझा की जा सकती है और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। ओबामा प्रशासन द्वारा शुरू की गई कनेक्टेड पहल का लक्ष्य यू.एस. में 99% छात्रों को हाई-स्पीड वायरलेस इंटरनेट से जोड़ना है। इसने टेक्नोलॉजी तक किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए स्कूलों और एडव, Mशमईरसफोट और जैसी तकनीकी कंपनियों को एक साथ लाया। हाथों-हाथ सीखना परियोजनाओं और इंटर्नशिप के माध्यम से वास्तविक दुनिया की समस्या-समाधान को एकीकृत करने से छात्रों को अपने डिजिटल कौशल को व्यावहारिक सेटिंग्स में लागू करने की अनुमति मिलती है, जिससे गहरी समझ और बेहतर ज्ञान प्रतिधारण सुनिश्चित होता है। फ़्यूचराइज़ जैसे इनोवेशन स्टूडियो विश्वविद्यालयों को इनोवेशन प्रोग्राम बनाने में सहायता करते हैं जो छात्रों को सहयोगात्मक रूप से काम करने और जटिल समस्याओं का समाधान बनाने के लिए एक साथ लाते हैं। छात्र डिजाइन सोच, शोध, आभासी कामकाज और संचार के आसपास कौशल विकसित करते हैं, जो डिजिटल दुनिया के लिए आवश्यक हैं। चल रहे शिक्षक विकास पुराने शिक्षकों को वर्तमान डिजिटल उपकरणों से अधिक परिचित होने की आवश्यकता हो सकती है। शिक्षकों के बीच डिजिटल कौशल अंतर को पाटने के लिए शैक्षिक क्षेत्र, समुदायों और मीडिया के साथ साझेदारी के माध्यम से जिला-स्तरीय पहल की आवश्यकता है। यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि शिक्षकों को आज के डिजिटल युग में डिजिटल साक्षरता को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन प्राप्त हों। डिजिटल साक्षरता का भविष्य आधुनिक दुनिया में युवाओं की रोजगार योग्यता के लिए डिजिटल साक्षरता तेजी से आधारशिला बनती जा रही है। वैश्विक नागरिकों के लिए डिजिटल कौशल की अपरिहार्यता न केवल संचार में बल्कि रोजगार हासिल करने, व्यापक शिक्षा और समावेशी समाज को बढ़ावा देने में भी इसकी भूमिका से रेखांकित होती है। जबकि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में डिजिटल साक्षरता शुरू करने के महत्व को मान्यता दी गई है, विश्व स्तर पर कई शैक्षिक प्रणालियाँ अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण जैसी चुनौतियों से जूझ रही हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस अंतर को पाटने के लिए वैश्विक पहल गतिमान हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) युवाओं और वयस्कों दोनों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कौशल से लैस करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा, 2025 तक 70% वयस्कों के पास बुनियादी डिजिटल कौशल सुनिश्चित करने का यूरोपीय संघ का लक्ष्य जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य डिजिटल रूप से साक्षर भविष्य की दिशा में एक सामूहिक कदम का संकेत देते हैं। लक्ष्यों को कार्रवाई में बदलने के लिए, विश्वविद्यालयों, सरकारों, गैर-लाभकारी संस्थाओं और तकनीकी कंपनियों को दुनिया भर के युवाओं को बेहतर शिक्षा के माध्यम से अपने डिजिटल कौशल को बढ़ाने में मदद करने के लिए एकजुट होना चाहिए।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद, एमएचआर मलोट - 152107 पंजाब

राय

'नैतिक नाकामी' के कारण

दिल्ली के भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख कर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने का आग्रह किया है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कई महीनों से जेल में बंद हैं, पांच महीने से कैबिनेट की बैठक तक नहीं हुई है और न ही विधानसभा सत्र बुलाया जा सका है। मुख्यमंत्री किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, लिहाजा दिल्ली के छठे वित्त आयोग का गठन नहीं किया जा सका है। यह संविधान का सरासर उल्लंघन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की कई रपटें सदन में पेश नहीं की जा सकी हैं। दिल्ली अद्र्धराज्य में संवैधानिक, प्रशासनिक, सरकार और अंततः जनता के स्तर पर बहुत कुछ ठप पड़ा है, लिहाजा इस सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। भाजपा विधायकों ने यह पत्र तब लिखा है, जब विधानसभा चुनाव मात्र 4-5 माह दूर हैं और बर्खास्तगी के बाद वैकल्पिक सरकार बनाना व्यावहारिक नहीं है। चूंकि पत्र विधायकों ने लिखा है, लिहाजा यह राजनीतिक कवायद है। राष्ट्रपति ऐसे पत्रों के आधार पर सरकारें बर्खास्त नहीं किया करते। अलबत्ता औपचारिकता निभाते हुए राष्ट्रपति ने वह पत्र गृह मंत्रालय को भिजवा दिया। यदि दिल्ली के उपराज्यपाल सरकार और राजधानी शहर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी रपट भेजते और राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते, तो उस पर गंभीर विचार किया जा सकता था। प्रधानमंत्री के साथ भी इस मुद्दे पर विमर्श किया जा सकता था। तब भी यह जरूरी नहीं था कि फाइल 'राष्ट्रपति भवन' भेजी ही जाती। दरअसल यह अध्याय केजरीवाल ने खुद लिखा है। बीते दोनों चुनावों में उनकी आम आदमी पार्टी (आप) को एकतरफा, प्रचंड बहुमत मिला था। दिल्लीवालों ने उसे एक अवसर देना तय किया था। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में जब मुख्यमंत्री को ही जेल जाना पड़ा, तो उससे पहले ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। यह केजरीवाल की 'नैतिक नाकामी' थी कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बेशक संविधान इस संदर्भ में खामोश है कि यदि एक मुख्यमंत्री को जेल होती है, तो उसकी संवैधानिक बाध्यता और व्यवस्था क्या होगी? शायद संविधान रचने वाले हमारे पुरखों ने इस स्थिति की कल्पना तक नहीं की थी कि भ्रष्टाचार के आरोप में किसी मुख्यमंत्री को, बिना सजा सुनाए, जेल में बंद करने की नौबत आ सकती है। सर्वोच्च अदालत की न्यायिक पीठ ने भी केजरीवाल की नैतिकता का फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया था। केजरीवाल को अदालत से जमानत भी नहीं मिल पा रही है। इन परिस्थितियों में केजरीवाल एक राष्ट्रवादी आंदोलनकारी की तरह हुंकार भरते रहे हैं कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। शायद उन्हें जानकारी नहीं थी कि जेल में हदबंदियां और पाबंदियां कितनी होती हैं! वह बैठक तक नहीं कर सकते थे। कैबिनेट की बैठक बुलाना निषेध था। मौखिक रूप से, अपनी पत्नी के जरिए, सरकार के मंत्रियों और 'आप' के ओहदेदारों को कितने निर्देश दे सकते थे? राष्ट्रीय राजधानी में इसके नतीजे सामने और स्पष्ट दिख रहे हैं। केजरीवाल ने अभी तक किसी भी नेता या विधायक पर भरोसा नहीं किया है कि वह उसे नया मुख्यमंत्री बनवा सकते। बेशक पूरी दिल्ली में अराजकता का माहौल है। गर्मियों में आम आदमी को पानी नसीब नहीं हुआ और उसे टैंकर के पानी के लिए हाथापाई तक उतरना पड़ा। मॉनसून का मौसम आया और बारिश होने लगी, तो दिल्ली पानी-पानी हो गई। सांसदों के अतिविशिष्ट क्षेत्र के घरों तक में पानी घुस गया। इतना जलजमाव और जलभराव हुआ कि 50 से अधिक मासूम लोगों की मौत तक हो गई। पानी में करंट तैरने लगा, जिसके संपर्क में आने से भी कुछ मौतें हुईं। चुनाव फरवरी, 2025 से पहले होने हैं। हमें नहीं लगता कि केंद्र सरकार 'राष्ट्रपति शासन' लगाने की पराकाष्ठा तक जाएगी। उससे केजरीवाल और 'आप' के पक्ष में सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा व्यक्तित्व परीक्षण घबराहट क्यों नहीं होने देना चाहे ?

विजय गर्ग

अभी चल रहे पर्सनैलिटी टेस्ट को कैसे क्रैक करें। आरंभ करने के लिए, उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन पत्र (डीएएफ) में अपने बयानों की विश्वसनीयता को उचित ठहराना होगा, जिसे उन्हें यूपीएससी मेन्स उत्तीर्ण करने के लिए अनिवार्य रूप से भरना होगा, पांच सदस्यों के बोर्ड का सामना करते समय अपने पैरों पर खड़े होकर सोचना होगा और वर्तमान के बारे में जानकारी रखनी होगी। मामले. आमतौर पर, 6-7 ऐसे बोर्ड होते हैं जो सार्वजनिक सेवाओं में करियर के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक साथ विभिन्न उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करते हैं और प्रत्येक उम्मीदवार का साक्षात्कार लगभग 30 मिनट तक चलता है। भले ही साक्षात्कार दौर में कुल 2025 में से 275 अंक होते हैं, जिस पर मेरिट सूची आधारित होती है, सिविल सेवा परीक्षा का यह अंतिम चरण उम्मीदवारों की सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में क्वालिफायर की संख्या में गिरावट आई है, जिसमें कुल 2529 उम्मीदवारों में से 36.89% (933 उम्मीदवार) उत्तीर्ण हुए; 2021 में, 1823 उम्मीदवारों में से 41.09% (749 उम्मीदवार) अधिक योग्य थे; जबकि 2020 में 2053 उम्मीदवारों में से 37.07% (761 उम्मीदवार) उत्तीर्ण हुए। पूर्व-कोविड वर्षों में, संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - 2019 में, 2034 उम्मीदवारों में से 45.58% (927 उम्मीदवार) ने परीक्षा उत्तीर्ण की; जबकि 2018 में 1992 उम्मीदवारों में से 40.76% (812 उम्मीदवार) उत्तीर्ण हुए। कुल मिलाकर, 63.11% उम्मीदवार 2022 में पर्सनैलिटी टेस्ट पास करने में असफल रहे, जो 2020 के बाद से सबसे अधिक है, जब 62.93% उम्मीदवार साक्षात्कार में सफल होने में असफल रहे। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है जिन्होंने 1982 में यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद सेवाओं में 35 साल बिताए, कहते हैं, "व्यक्तित्व परीक्षण की कठोरता से निपटने के लिए, उम्मीदवारों को मॉक सत्र में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें अभ्यास करने में मदद मिलती है कि उन्हें खुद को कैसे संचालित करना है, इससे उन्हें परिचित होना पड़ता है।" प्रश्न स्वयं को सही करने के तरीकों पर सलाह देते समय, चाहे यह उनकी उचित उच्चारण की कमी हो या यहां तक कि हकलाना हो जो उनके विचारों को व्यक्त करते समय विकसित हो सकता है। चूंकि कुछ कोचिंग संस्थान मुफ्त मॉक सत्र प्रदान करते हैं, इसलिए छात्रों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने और 15 मॉक सत्रों में भाग लेने के लिए जाना जाता है। साक्षात्कारकर्ता, जो अधिकतर पूर्व सिविल सेवक या अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, उम्मीदवारों से कम से कम तीन श्रेणियों में पूछताछ करते हैं: डीएएफ के आधार पर उम्मीदवारों की शैक्षिक/पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका वैकल्पिक विषय और सामान्य ज्ञान। "इनमें से किसी भी अनुभाग में तैयारी की कमी उम्मीदवारों को परेशान कर सकती है। चूंकि साक्षात्कार आत्मविश्वास और ज्ञान के बीच एक स्पष्ट समीकरण है, इसलिए उम्मीदवारों को इन पर सचेत रूप से काम करने की आवश्यकता है," इस बात पर जोर देते हुए कि छात्र अपनी दक्षता के स्तर के आधार पर अंग्रेजी या हिंदी में उत्तर दे सकते हैं, इसलिए यदि वे योग्य हैं तो भाषा कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक में लिखित परीक्षा। डीएएफ को समझदारी से भरना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे अस्पष्ट और खुला रखना केवल उम्मीदवारों के लिए परेशानी को आमंत्रित करना होगा। दादू कहते हैं, छात्रों को सामान्य ज्ञान के सवालों से सबसे अधिक चुनौती महसूस होती है, और यदि वे केंद्रीय बजट के बाद साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो रहे हैं, तो उन्हें उस विषय पर ढेर सारे सवालों का जवाब देना पड़ सकता है, और आगे बताते हुए कि उम्मीदवारों को व्यापक जानकारी के लिए इकोनॉमिस्ट पत्रिका पढ़नी चाहिए। आर्थिक और राष्ट्रीय समाचारों को कवर करने वाले कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विश्लेषण। प्रश्न आज के ज्वलंत मुद्दों पर हो सकते हैं जैसे 'क्या भारत का नाम बदलकर भारत किया जाना चाहिए', या 'क्या आप एक राष्ट्र के बारे में सोचते हैं ?एक सर्वेक्षण आवश्यक है', जिसके लिए छात्रों को विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए, चरम स्थिति न लेते हुए संतुलन, परिपक्वता और चातुर्य का अभ्यास करना चाहिए, इंजीनियरिंग से अधिक कला आम धारणा के विपरीत, साक्षात्कार में कला स्नातकों को इंजीनियरिंग स्ट्रीम के उम्मीदवारों पर बढ़त मिलती है क्योंकि उन्हें उन इंजीनियरों की तुलना में बेहतर संचार कौशल के लिए जाना जाता है जो लिखित (प्रारंभिक और मुख्य) परीक्षाओं में अधिक कुशल होते हैं।" प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, राजेश कुमार पाठक (1995 बैच) कहते हैं, ₹यूपीएससी परीक्षा के टॉपर्स जरूरी नहीं कि इंजीनियर हों, और यह किसी की शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर अंक नहीं देता है, बल्कि उम्मीदवार के समग्र व्यक्तित्व के आधार पर अंक देता है।₹ प्रौद्योगिकी, विस्तार से बताती है कि छात्रों को ईमानदार होना चाहिए और उचित डेटा के साथ अपनी राय का समर्थन करना चाहिए। अपने डीएएफ को अच्छी तरह से जानने के अलावा, उन्हें अपने गृह जिलों/शिक्षा के स्थान और समसामयिक और विवादास्पद मामलों पर सरकार के दृष्टिकोण के बारे में खुद को अपडेट करना चाहिए, उम्मीदवारों से विचार और तार्किक सोच की स्पष्टता प्रदर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है। तैयारी की रणनीति इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाले प्रत्येक आईआईटी छात्र के लिए, आईएएस से मेल खाने वाला एक दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज का छात्र है, कहते हैं, "व्यक्तित्व परीक्षण में चयन के प्रमुख मानदंड एक उम्मीदवार के बुनियादी ज्ञान से परे जाकर यह जांचते हैं कि क्या वह / उसके पास विशिष्ट सेवाओं का हिस्सा बनने और हाथ में काम के साथ न्याय करने की बुद्धिमत्ता है। यही कारण है कि व्यापक ज्ञान के बाद भी, साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले लगभग 10 छात्रों में से 6 में उत्तीर्ण न होने की प्रवृत्ति होती है, हालांकि उनके पास यूपीएससी मेन्स में औसत और उससे अधिक अंक हो सकते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उम्मीदवारों को अपने सामान्य ज्ञान कौशल को निखारने के लिए व्यापक विषयों पर पढ़ना चाहिए, चाहे वह ऑनर किलिंग हो या यूक्रेन-रूस युद्ध, वेनेजुएला-गुयाना झगड़ा, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण या यहां तक कि यूएफओ। ₹कम समय में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव तीव्र हो सकता है, जिससे उम्मीदवारों के लिए संयमित और स्पष्ट रहना अनिवार्य हो जाता है।₹ पिछले कुछ वर्षों में, उम्मीदवारों का अधिक व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण के प्रारूप में सूक्ष्म परिवर्तन हुए हैं। पहले, साक्षात्कार मुख्य रूप से बौद्धिक गुणों का आकलन करने पर केंद्रित था, लेकिन वर्तमान प्रारूप उम्मीदवार के व्यक्तित्व के समग्र मूल्यांकन पर जोर देता है, वह आगे कहते हैं, साक्षात्कार में सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर नहीं है कि उम्मीदवार शहरी महानगर से आता है या छोटे से। शहर। "हालांकि शहरी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के पास संसाधनों और विविध दृष्टिकोणों तक अधिक पहुंच हो सकती है, लेकिन यह स्वचालित रूप से उन्हें साक्षात्कार में सफल होने में अधिक कुशल नहीं बनाता है। छोटे शहरों के छात्र अक्सर अद्वितीय अनुभव और दृष्टिकोण लेकर आते हैं, और उनकी चुनौतियाँ और जीतें भी उतनी ही मूल्यवान हो सकती हैं। सफलता विषय वस्तु की गहरी समझ, आलोचनात्मक सोच कौशल, प्रभावी संचार और एक पूर्ण व्यक्तित्व जैसे कारकों के संयोजन पर निर्भर करती है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

व्यवसाय में सफलता के बिंदु : विजय गर्ग

विजय गर्ग

कई युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे सफल नहीं हुए तो क्या होगा। ऐसी सोच आत्मविश्वास की कमी पर आधारित है। ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कई युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे सफल नहीं हुए तो क्या होगा। ऐसी सोच आत्मविश्वास की कमी पर आधारित है। ईमानदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्यवसाय मेंयहां सफलता के सात बिंदु दिए गए हैं, जिन्हें इंद्रधनुष कहा जाता है। इन पर अमल करके निश्चित सफलता हासिल की जा सकती है। इच्छाशक्ति/प्रतिबद्धता व्यवसाय में सफलता के लिए इच्छाशक्ति आवश्यक है। अपना पेशा चुनने के बाद यदि आप दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे यह पेशा करना है, मैं कर सकता हूं और इसमें सफलता हासिल करूंगा तो सफलता मिलना तय है। वही मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जिसे अपनी मंजिल का पता होता है। प्रकृति ने हर मनुष्य को शक्ति रूपी एक बोर्ड दिया है, जिस पर बैठकर वह अपना काम कर सकता हैएम लिखते हैं कर्म करने की शक्ति लगभग सभी में एक जैसी होती है, लेकिन कर्म करने की इच्छा व्यक्ति के वश में होती है। जो व्यक्ति कर्मशक्ति का भरपूर उपयोग करता है और लगन से कार्य करता है, सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। बिना मेहनत के कोई उपलब्धि नहीं मिलती बिना मेहनत के कोई उपलब्धि नहीं मिलती. यह उपलब्धि तभी हासिल हो सकती है जब हम ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें और कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत मानव शक्ति है. अगर कोई आज का काम कल पर छोड़ देता है तो कल के कारण उसका काम कभी पूरा नहीं होतातो यह कभी नहीं आता. कभी-कभी अगर आपको हार का सामना करना पड़े तो घबराना नहीं चाहिए और मैदान छोड़ देना चाहिए। हार से डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मन में लगन और चाहत हो तो समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। आत्मविश्वास की जरूरत व्यवसाय में सफलता काफी हद तक आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, उसके इरादे कभी पूरे नहीं हो सकते। वह निर्णय लेने में झिझकता है और कभी भी किसी भी कार्य को पूरे उत्साह के साथ नहीं कर पाता है। कभी-कभी व्यापार में ठहराव आ सकता है. इसे देखकर निराश नहीं होना चाहिए बल्कि इसके कारणों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करना चाहिए। अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो समस्याओं का समाधान मिल ही जाता है। ईमानदारी प्रत्येक कार्य को इस संकल्प के साथ शुरू करना चाहिए कि भले ही मुझे कोई रास्ता न मिले, मैं नया रास्ता बना लूंगा लेकिन सफलता अवश्य प्राप्त करूंगा। ईमानदारी से की गई मेहनत से हासिल की गई सफलता स्थाई होती है। बेईमानी या हेराफेरी से की गई कमाई तात्कालिक खुशी तो दे सकती है, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती। आत्मा बोझिल है,जिसका एहसास हमेशा परेशान करने वाला होता है. व्यवसाय में विशेषज्ञता आवश्यक है किसी भी पेशे में सफलता के लिए ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ-साथ उस पेशे में विशेषज्ञता भी जरूरी है। बिना स्किल के बिजनेस ठीक से नहीं चल पाएगा. अगर आपको अपने प्रोफेशन के बारे में पूरी जानकारी होगी तो मेहनत का फल तभी मिलेगा। जो लोग अपने चुने हुए पेशे में महारत हासिल करके प्रसिद्धि हासिल करते हैं उनमें ईमानदारी, परिश्रम और कड़ी मेहनत जैसे गुण होते हैं। सफलता के लिए आपको हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। ज्ञान का चक्रयदि यह हल्का हो तो व्यापार में रुकावट आती है। भाषण की भूमिका संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास बोलने की शक्ति है। कविता की शक्ति सहयोगियों का दिल जीत सकती है, लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग सहयोगियों और ग्राहकों को अलग-थलग कर देता है। मीठा बोलने में न तो कुछ खर्च होता है और न ही कोई बड़ा प्रयास करना पड़ता है। धीरे-धीरे बोलने या क्रोध करने पर शरीर की शक्ति आवश्यकता से अधिक लगती है, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, आयु भी कम हो जाती है। व्यवसाय और सहकर्मियों में सफलताप्यार और सम्मान पाने के लिए धीरे बोलने की कोशिश न करें, बल्कि मीठा बोलने का अभ्यास करें। अद्यतित रहें इन सबसे ऊपर उभरती हुई कला है। जो व्यक्ति सुख-दुख में भी चढ़ने की कला में रहता है, वह कभी असफल नहीं हो सकता। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम दुख की घड़ी में भी आशा की किरण के साथ धन्यवाद दें तो कठिन समय अपने आप दूर हो जाएगा। जिंदगी चलते रहने का नाम है. जो साहस खो देता है वह शर्त हार जाता है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के माध्यम सेजो व्यक्ति लग्न में रहते हुए जीवन के लिए संघर्ष करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। साहस और उद्यम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बादल कितने भी घने क्यों न हों, सूर्य की किरणें अवश्य चमकती हैं। इसलिए कभी भी निराशा को अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए। लालच में आकर कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। गलतियाँ हर इंसान से होती है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करता है। सफल लोगों का प्रवाह नदी की तरह होता है। मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करनी हैवास्तविक कार्य करते समय व्यक्ति को हमेशा प्रगति की स्थिति में रहना चाहिए। जो लोग खुशियां बांटते हैं, जरूरत के वक्त दूसरों की मदद करते हैं, वही आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं। लालच में पड़कर गलत तरीकों से की गई कमाई से जीवन के सुख तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सुख और आनंद प्राप्त नहीं होता। हमेशा ईमानदारी से मेहनत करके कमाई करें।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

क्या विकास के लिए धीमा जहर है रेवड़ी कल्चर ?

हिमाचल ने राज्यों के लिए बजाई खतरे की घंटी

परिवहन विशेष न्यूज

भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जन कल्याणकारी योजनाओं की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन यह चेतने का समय है कि सरकारें बेछूट रेवड़ी गैर-उत्पादक खर्च से बचाव का रास्ता निकालें। भारत जैसे देश में हर तीसरे महीने किसी न किसी विधानसभा चुनाव हो रहा होता है। इस नाते राजनीतिक दलों में चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी संस्कृति बढ़ती जा रही है जो चिंता की बात है।

नई दिल्ली। अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश चर्चा में है। मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट और कई अन्य शीर्ष पदाधिकारियों का वेतन दो महीने के लिए लंबित कर दिया गया है तो कर्मचारियों के वेतन सप्ताह भर और पेंशन लगभग दस दिन विलंबित रहे क्योंकि फंड नहीं था। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस कवायद से महीने में तीन चार करोड़ रुपये की बचत कर लेगी। इसे वित्तीय अनुशासन का नाम दिया जा रहा है जबकि यह लाचारगी और बेबसी है क्योंकि डीजल पर वैट बढ़ाने से लेकर दूसरी कई सेवाओं में टैक्स बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है।

हिमाचल तो एक उदाहरण है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य हैं जो कर्ज के बोझ में इतने दबते जा रहे हैं कि देर हुई तो जनता को ही भुगतना होगा। वहीं, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड जैसे राज्य भी हैं जिनको तत्काल अपने राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय ढूंढने होंगे। या फिर तत्काल खर्च कटौती की राह पर चलना होगा। हिमाचल ने एक चेतावनी दी है, पूरे देश को इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देनी चाहिए वरना हर किसी को हर्जाना भरना पड़ सकता है।

राज्यों के वित्तीय हालात और इसमें सुधार की जरूरत पर दैनिक जागरण शनिवार से खबरों के एक अभियान की शुरूआत कर रहा है। वैश्विक स्तर पर यूं तो कई उदाहरण होंगे लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला सबसे ज्वलंत उदाहरण है जो भ्रष्टाचार के साथ साथ अपनी गलत नीतियों, रेवड़ियों और वक्त रहते निवेश के अभाव के कारण सबसे अमीर देशों की श्रेणी से घटकर वित्तीय संकट के काल में पहुंच गया।

भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जन कल्याणकारी योजनाओं की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन यह चेतने का समय है कि बेछूट रेवड़ी, गैर उत्पादक खर्च से बचाव का रास्ता निकालें। भारत जैसे देश में हर तीसरे महीने किसी न किसी विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है और इस नाते राजनीतिक दलों में चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी संस्कृति बढ़ती जा रही है। भले ही इसके लिए राज्यों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है।

नतीजा यह है कि हर राज्य अपने राजस्व प्राप्ति का 80 फीसद तो सैलरी, पेंशन जैसे फिक्स्ड खर्च पर ही व्यय कर रहा है। औसतन 20 फीसद सामाजिक और विकास कार्यों के लिए बच रहा है। एक उदाहरण तो कर्नाटक जैसे विकसित राज्य का भी है जहां राजस्व प्राप्ति से अधिक फिस्क्ड खर्च है। लिहाजा विकास कार्यों पर साल भर से लगभग रोक जैसी स्थिति है। इससे बाहर आने के लिए राज्य सरकारें अलग अलग मद में टैक्स बढ़ाती है या फिर सेवाओं की गुणवत्ता खराब होती है। जरूरत है फिस्क्ड खर्च घटाने की और आमदनी बढ़ाने की।

स्पष्ट है कि मुफ्त कुछ भी संभव नहीं है। आज की रेवड़ी और सब्सिडी का लाभ अगर आप ले रहे हैं तो सूद समेत उसका भुगतान अगली पीढ़ी को करना ही होगा। राजनीतिक दलों को भी इसका अहसास होना चाहिए कि लोकलुभावन घोषणाएं उस तक ही सीमित होनी चाहिए जितनी पूरी हो सकती है।चुनाव आयोग ने कुछ वर्ष पूर्व सुझाव दिया था कि घोषणापत्र में जो दावे किए जाते हैं उसे पूरा करने का वित्तीय रोडमैप भी बताया जाना चाहिए। यानी राजनीतिक दल राज्यों की वित्तीय स्थिति को समझें। निवेश के रास्ते अपनाएं, जनता को सहूलियत के साथ राजस्व बढ़ाएं। खजाने की कीमत पर न तो राजनीति होनी चाहिए न ही शासन।

खुदरा महंगाई में मामूली इजाफा, औद्योगिक उत्पादन के डेटा ने किया निराश

खुदरा महंगाई दर अगस्त महीने में मामूली बढ़कर 3.65 प्रतिशत रही। यह आरबीआइ द्वारा निर्धारित लक्ष्य के दायरे में है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2024 में 3.6 प्रतिशत थी जबकि बीते वर्ष अगस्त में यह 6.83 प्रतिशत थी। वहीं खनन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन से जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सुस्त पड़कर 4.8 प्रतिशत पर आ गई।

नई दिल्ली। खुदरा महंगाई में जुलाई के मुकाबले में मामूली इजाफा देखने को मिला। हालांकि, यह लगातार दूसरे महीने काबू में रही। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 3.65 फीसदी रही, जो जुलाई में 3.60 फीसदी थी। इसमें 0.05 फीसदी का मामूली इजाफा हुआ है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति उम्मीद से थोड़ा अधिक रही, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। समाचार एजेंसी रॉयटर्स एक सर्वे में अर्थशास्त्रियों ने अगस्त में खुदरा महंगाई दर 3.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था।

जुलाई में मिली थी बड़ी राहत : खुदरा महंगाई दर जुलाई में करीब 5 साल के लंबे अंतराल के बाद आरबीआई के 4 फीसदी के लक्ष्य से नीचे आई थी। ऐसे में यह लगातार दूसरा महीना रहा, जब खुदरा महंगाई 4 प्रतिशत से नीचे रही। केंद्र सरकार ने आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी दी हुई है।

खाद्य वस्तुओं में मामूली बढ़ोतरी: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के डेटा के मुताबिक, खाद्य वस्तुओं की महंगाई अगस्त महीने में मामूली इजाफे के साथ 5.66 फीसदी रही। यह जुलाई में 5.42 फीसदी थी। फूड महंगाई दर की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में आधी हिस्सेदारी रहती है।

सब्जियों की महंगाई दर अगस्त में 10.71 फीसदी बढ़ी। यह इससे पिछले महीने 6.83 प्रतिशत थी। इसका मतलब कि सब्जियों का भाव बढ़ा है। इसकी वजह अनियमित मानसून हो सकती है, जिसका उपज और आपूर्ति पर असर पड़ा। दालों और अनाजों के लिए महंगाई दर क्रमशः 13 फीसदी और 7.31 फीसदी रही। फलों की महंगाई दर 6.45 फीसदी थी। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अगस्त में महंगाई दर 2.98 फीसदी थी। मांस और मछली, अंडा की कीमतों में नरमी दिखी।

यस बैंक के शेयरों में क्यों नहीं आ रहा उछाल, क्या यहां फंसा है मामला?

प्राइवेट सेक्टर का यस बैंक साल 2020 की शुरुआत में डूबने की कगार पर पहुंच गया था। इसे बचाने के लिए आरबीआई ने स्थानीय बैंकों का एक ग्रुप बनाया और उन्होंने निवेश करके यस बैंक बचाया। SBI के पास यस बैंक में सबसे अधिक 24 फीसदी हिस्सेदारी है। SBI अब यस बैंक से बाहर निकलने की तैयारी में है। लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते डील मुश्किल हो सकती है।

नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक का शेयर काफी समय से सुस्त पड़े हैं। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने सिर्फ 2.63 फीसदी का मुनाफा दिया है। एक महीने की बात करें, तो निवेशकों को करीब चार फीसदी का नेगेटिव रिटर्न मिला है। दरअसल, यस बैंक में एसबीआई अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में है। उसे आरबीआई ने इजाजत भी दे दी है।

लेकिन, यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के इच्छुक बोलीदाता 51 फीसदी स्टेक खरीदना चाहते हैं, लेकिन यह बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई के नियमों के खिलाफ है और वह इसकी मंजूरी नहीं दे रहा। अगर यह डील हो जाती, तो मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार यस बैंक के शेयरों में तेजी आने की उम्मीद थी।

क्या यस बैंक में हिस्सेदारी नहीं बिकेगी?

निजी क्षेत्र के यस बैंक में हिस्सेदारी खरीद की प्रक्रिया बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने पर बोलीदाताओं के जोर देने की वजह से खतरे में पड़ सकती है। समाचा एजेंसी पीटीआई ने इस पूरे घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति से पूछा कि क्या चालू वित्त वर्ष के अंत तक यह सौदा पूरा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि सौदा फंस सकता है। सूत्र के मुताबिक, आरबीआई इस बात से असहज है कि एक विदेशी संस्था के पास यस बैंक जैसी बड़ी वित्तीय संस्था में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हो। जापान की एसएमबीसी और अमीरात एनबीडी के रूप में दो बोलीदाता मैदान में हैं। यस बैंक में नियंत्रक हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने वाले दोनों दावेदार सीधे आरबीआई से बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक इसका स्वामित्व नियंत्रण देने के लिए तैयार नहीं है।

क्या हैं बैंक में हिस्सेदारी के नियम?

मौजूदा नियमों के मुताबिक, किसी भी बैंक में किसी इकाई के पास अधिकतम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति है और इस सीमा से अधिक हिस्सेदारी वाले मामलों में इसे कम करने के लिए एक निश्चित समयसीमा निर्धारित की गई है।

जेपी एसोसिएट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू, लेनदार बैंकों ने डेलाइट को सौंपी जिम्मेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) जेपी एसोसिएट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति पहले ही दे चुकी है। जयप्रकाश एसोसिएट के पास सीमेंट प्लांट रियल एस्टेट विभिन्न शहरों में आवासीय भवन होटल अस्पताल और देश का एकमात्र फार्मूला वन रेस ट्रैक है। देनदारी को चुकाने के लिए संपतियों की बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन का काम अब पीडब्ल्यूसी की जगह डेलाइट देखेगी।

नई दिल्ली। जयप्रकाश एसोसिएट्स की दिवालिया प्रक्रिया के समाधान और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी के लिए कर्जदाता बैंकों ने डेलाइट (Deloitte) का चयन किया है। जेपी एसोसिएट पर 51,509 करोड़ की देनदारी है। और माना जा रहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी दिवालिया प्रक्रिया है।

जेपी एसोसिएट पर एसबीआई, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई बैंक का सबसे अधिक उधार है। कंपनी के कुल बकाए में इन तीन बैंकों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा अन्य 31 कर्जदाताओं के कर्ज कंपनी पर है।

नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) जेपी एसोसिएट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति पहले ही दे चुकी है। जयप्रकाश एसोसिएट के पास सीमेंट प्लांट, रियल एस्टेट, विभिन्न शहरों में आवासीय भवन, होटल, अस्पताल और देश का एकमात्र फार्मूला वन रेस ट्रैक है। सूत्रों के मुताबिक देनदारी को चुकाने के लिए संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन का काम अब पीडब्ल्यूसी की जगह डेलाइट देखेगी।

जेपी एसोसिएट को उधार देने वालों ने भुवन मदान को रेजोल्यूशन (दिवालिया समाधान) प्रोफेशनल नियुक्त किया है। डेलाइट संपत्ति की बिक्री और दिवालिया प्रक्रिया के समाधान को लेकर योजना तैयार करेगी। उधारकर्ताओं ने कानूनी फर्म शार्दूल अमरचंद मंगलदास को कानूनी सलाहकार नियुक्त करने की मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक जेपी एसोसिएट पर एसबीआई का कर्ज 15,465 करोड़ का है।

इसके साथ कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक को 9203 करोड़ तो आईडीबीआई बैंक को 5794 करोड़ रुपए लौटाने हैं। जेपी एसोसिएट के सीमेंट प्लांट की क्षमता 90 लाख टन की बताई जाती है। कंपनी के पास दिल्ली, नोएडा, मसूरी व आगरा जैसे शहरों में होटल है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का घाटा 1023 करोड़ का रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह घाटा 181 करोड़ का था।

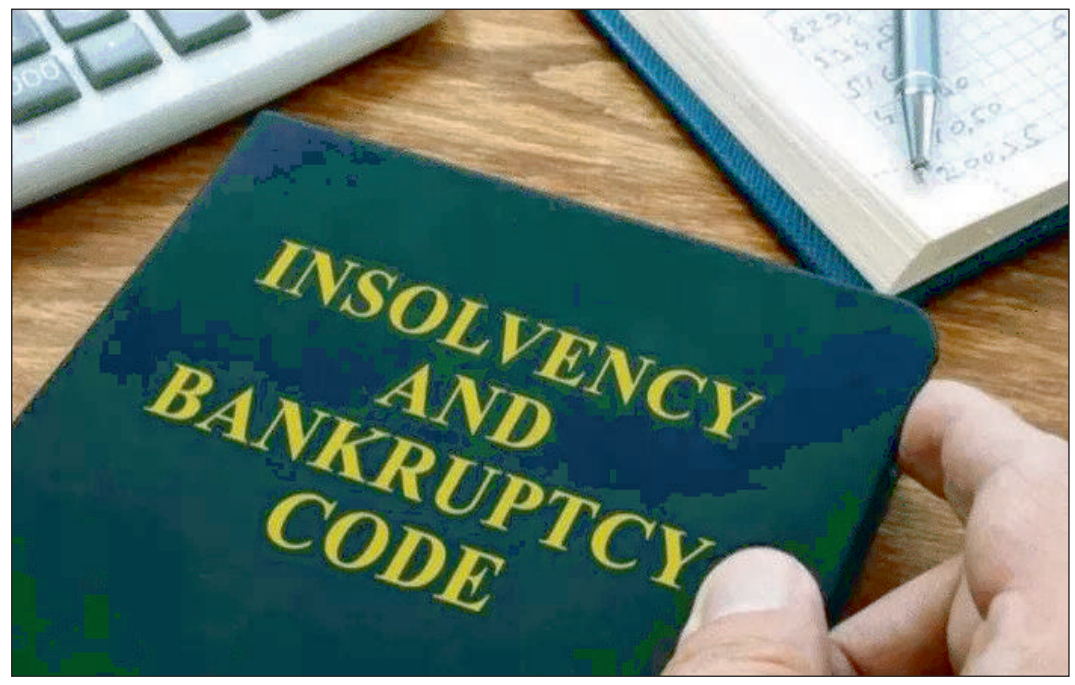

भारत का बढ़ेगा आर्थिक दबदबा, तीन साल में जापान-जर्मनी से निकल सकता है आगे

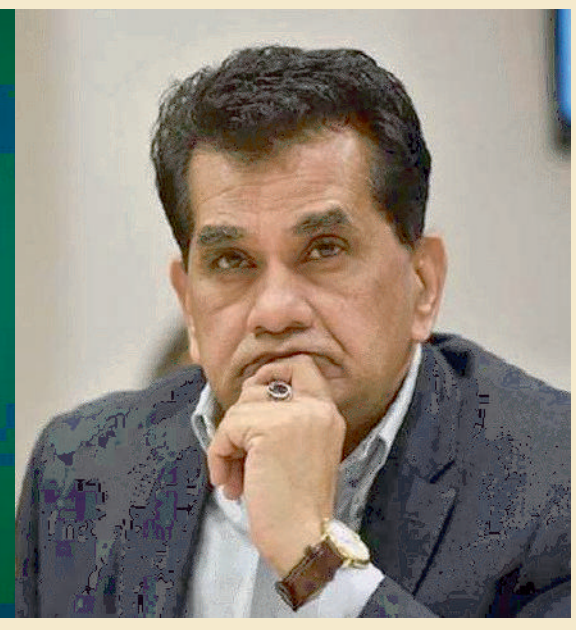

भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों से बड़ी हो सकती है। जी20 शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश के जरिये भारत अगले एक दशक में वैश्विक विकास वृद्धि में 20 प्रतिशत का योगदान देगा। उन्होंने कहा कि भारत को अगले तीन दशकों में 9-10 प्रतिशत की दर से विकास करना होगा।

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछली कुछ तिमाहियों में तो इसने प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों के अनुमान से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत फिलहाल दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन, यह जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। फिर भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका रहेंगे।

जी20 शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश के जरिये भारत अगले एक दशक में वैश्विक विकास वृद्धि में 20 प्रतिशत का योगदान देगा। जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने एआईएमए के सम्मेलन में कहा, 'अगले तीन सालों में हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। खास बात यह है कि जहां विकास के लिए दुनिया तरस रही है वहीं इस दौरान भारत एक बहुत ही लचीली शक्ति के तौर पर उभरा है।'

आज जो हम देख रहे हैं, वह हमारी आर्थिक स्थिति में एक पीढ़ी में एक बार होने वाला बदलाव है। कुछ साल पहले हम नाजुक दौर से गुजर रहे थे और आज हम शीर्ष पांच में शामिल हैं। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को बदलने, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने और पोषक मानकों को बढ़ाना होगा। भारत को भविष्य में विकास को गति देने के लिए कई विकसित प्रदेशों की जरूरत होगी।

अमिताभ कांत ने कहा, "अगर भारत को अगले तीन दशकों में 9-10 प्रतिशत की दर से विकास करना है और 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है, तो हमें बहुत बड़े पैमाने पर सुधार करने होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य, जो देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें बदलने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि भारत की शीर्ष 50 प्रतिशत आबादी वास्तव में विकास और समृद्धि को बढ़ावा देती है। नीचे की 50 प्रतिशत आबादी मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वह कृषि मजदूरी या सरकारी कल्याण योजनाओं पर निर्भर है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम निचले 50 प्रतिशत लोगों के जीवन में बदलाए लाएं।

सेंसेक्स ने पहली बार छुआ 83,000 का स्तर, निफ्टी का भी नया रिकॉर्ड; मालामाल हुए निवेशक

परिवहन विशेष न्यूज

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में भारती एयरटेल एनटीपीसी जेएसडब्ल्यू स्टील महिंद्रा एंड महिंद्रा अदाणी पो र्ट्स टेक म¨हद्रा लार्सन एंड टुब्रो टाटा स्टील भारतीय स्टेट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सबसे अधिक लाभ में रहे। प्रमुख कंपनियों में नेस्ले एकमात्र कंपनी रही जिसमें गिरावट रही। शेयर मार्केट के 2335 शेयरों में तेजी दर्ज की गई वहीं 1612 शेयर गिरकर बंद हुए।

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी आई। बीएसई सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान पहली बार 83,000 के स्तर को लांघ गया। एनएसई निफ्टी भी अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच प्रमुख कंपनियों के शेयरों में लिवाली और विदेशी पूंजी प्रवाह से बाजार में तेजी आई। शेयर मार्केट की इस बहार में निवेशकों की संपत्ति 6.59 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स कारोबार समाप्ति से पहले अच्छी लिवाली के चलते पहली बार 83,000 के पार पहुंच गया। सूचकांक कारोबार समाप्ति से एक घंटे पहले 1,593.03 अंक यानी 1.95 प्रतिशत उछलकर रिकॉर्ड 83,116.19 अंक पर पहुंच गया। अंत में यह 1,439.55 अंक यानी 1.77 प्रतिशत चढ़कर अपने अब तक के उच्चतम स्तर 82,962.71 पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 470.45 अंक यानी 1.89 प्रतिशत के उछाल के साथ रिकॉर्ड 25,388.90 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के ज्यादातर समय खरीद-बिक्री हल्की रही। कारोबार के अंतिम एक-दो घंटों में सभी क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के शेयरों में ताबड़तोड़ लिवाली से बाजार ऊपर चढ़ा।

मानक सूचकांक कारोबार के दौरान 514.9 अंक चढ़कर रिकार्ड 25,433.35 अंक तक चला गया था। निफ्टी और सेंसेक्स मजबूती के साथ खुले और दोपहर तक एक दायरे में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कास्पी, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग अच्छी बढ़त में रहे जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट मामूली नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में कारोबार के दौरान तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 398.13 अंक टूटा था जबकि एनएसई निफ्टी में 122.65 अंक की गिरावट आई थी।

नेस्ले गिरावट वाली इकलौती कंपनी

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में भारती एयरटेल, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदाणी पोर्ट्स, टेक म¨हद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, भारतीय स्टेट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सबसे अधिक लाभ में रहे। प्रमुख कंपनियों में नेस्ले एकमात्र कंपनी रही जिसमें गिरावट रही। शेयर मार्केट के 2,335 शेयरों में तेजी दर्ज की गई, वहीं 1,612 शेयर गिरकर बंद हुए। 122 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 278 शेयरों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चस्तर को छुआ, जबकि 36 शेयरों ने 52-सप्ताह के न्यूनतम स्तर को टच किया।

फेड के लिए कटौती का रास्ता साफ

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा, 'अमेरिका में मुद्रस्फीति के आंकड़े बाजार के लिहाज से कुछ सकारात्मक रहे हैं। अगस्त में मुद्रास्फीति बढ़ने की रफ्तार धीमी होकर 2.5 प्रतिशत रही जो इससे पहले 2.9 प्रतिशत थी।'

उन्होंने कहा, 'इससे फेडरल रिजर्व के सितंबर में मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कमी का रास्ता साफ हुआ है। चूंकि मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत पर ऊंची बनी हुई है, ऐसे में फेडरल रिजर्व सतर्क रह सकता है और संभवतः ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती नहीं करेगा और 0.25 प्रतिशत कटौती का विकल्प चुन सकता है।

संस्कारशाला: बच्चों और युवाओं का सांस्कृतिक अनुष्ठानों में जुड़ाव क्यों है महत्वपूर्ण

डॉ. अंकुर शरण

आज की तेज़-तर्रार ज़िंदगी में, जहां तकनीक और आधुनिकता ने हमारी दिनचर्या को बदल दिया है, वहीं सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है। बच्चों और युवाओं को इन अनुष्ठानों में शामिल करना बेहद आवश्यक है ताकि वे अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं से जुड़े रहें। इन अनुष्ठानों में न केवल आस्था होती है बल्कि यह हमारी जड़ों से जुड़ने का माध्यम भी है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है।

अनुष्ठानों का सांस्कृतिक महत्व

भारत एक ऐसा देश है, जहां हर कोने में अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। धार्मिक अनुष्ठान न केवल आस्था का प्रतीक होते हैं, बल्कि यह हमें अनुशासन, विनम्रता, और एकता की शिक्षा भी देते हैं। आजकल, कई लोग मंदिरों और धार्मिक स्थलों को सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट के रूप में देखते हैं। लोग अनजाने में ही इन स्थानों पर असामान्य वस्त्र जैसे शॉर्ट्स या अन्य अनुचित परिधान पहनकर जाते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत है।

मंदिर और धार्मिक स्थल हमारी श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक होते हैं, और यहां पहुंचने पर हमें अपने आचरण और वेशभूषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर अनुशासन और मर्यादा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह न केवल हमारे समाज के प्रति सम्मान दर्शाता है बल्कि हमें हमारी जड़ों से भी जोड़ता है।

व्यवहार से परिलक्षित होती है शिक्षा

बच्चों और युवाओं को संस्कारों का महत्व समझाना हमारी जिम्मेदारी है। यह ज़रूरी नहीं है कि हर बात उन्हें सिखाई जाए, कई बातें उनके सामने उदाहरण बनकर सिखाई जाती हैं। हमारे सार्वजनिक स्थानों पर किए गए आचरण से हमारी असली शिक्षा प्रकट होती है। सार्वजनिक स्थानों पर हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह हमारे चरित्र और शिक्षा का सजीव उदाहरण होता है।

मंदिर जैसे पवित्र स्थलों पर सम्मानपूर्वक आचरण करना हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी सही दिशा में प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी संस्कृति का आदर कैसे करें और आने वाली पीढ़ियों को भी यही मूल्य सिखाएं।

बच्चों और युवाओं की भागीदारी क्यों है आवश्यक

आजकल के बच्चों और युवाओं का धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में सक्रिय भाग लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें हमारी परंपराओं, धर्म और सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति सम्मान दिखाने का मौका देता है। जब बच्चे इन अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, तो वे इनकी महत्ता को समझते हैं और यह उन्हें समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है।

इसलिए, यह हम पर निर्भर है कि हम उन्हें इन अनुष्ठानों का हिस्सा बनाएं और उन्हें यह सिखाएं कि मंदिर केवल पूजा करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, संस्कार, और आस्था के प्रतीक हैं। यहाँ हमें न केवल अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए बल्कि अपने समाज और अपनी जड़ों के प्रति सम्मान भी दिखाना चाहिए।

संक्षेप में, बच्चों और युवाओं को सांस्कृतिक अनुष्ठानों में शामिल करना, उन्हें अपने मूल्यों और परंपराओं से जोड़े रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह उन्हें सिखाता है कि जीवन में अनुशासन, मर्यादा, और सामाजिक सम्मान का कितना महत्व है।

वंदे भारत के बाद अब दौड़ने के लिए तैयार वंदे मेट्रो, पहली ट्रेन को PM मोदी करेंगे रवाना; पढ़ें खासियत

परिवहन विशेष न्यूज

वंदे भारत के बाद अब वंदे मेट्रो ट्रेनें भी भारतीय रेलवे की शान बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें आसपास के दो शहरों के सफर को बेहद आसान बना देंगीं और इनमें जनता की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पहली ट्रेन को पीएम मोदी सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

नई दिल्ली। आसपास के दो शहरों के बीच आना-जाना अब बेहद आसान होने वाला है। वंदे भारत की तर्ज पर डिजाइन किया गया भारत की पहली स्वदेसी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे मेट्रो का इंतजार खत्म होने जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी जन्मतिथि से एक एक दिन पहले 16 सितंबर को भुज एवं अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। स्वदेसी तकनीक से निर्मित यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है। जल्द ही मध्यम दूरी के अन्य शहरों के लिए भी ऐसी ट्रेनें चलाई जाएंगी।

वंदे भारत की तर्ज पर किया गया है निर्माण

वंदे मेट्रो का निर्माण वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तर्ज पर किया गया है, जिसे लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो शहरों में आवागमन को आसान करना है। रोजाना आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोग, छात्र एवं कारोबारी इस फासले को तीन से चार घंटे में आराम से तय कर सकेंगे।

कुल 12 वातानुकूलित डिब्बे वाली इस ट्रेन की अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रतिघंटा है। पिछले हफ्ते अहमदाबाद-गांधीधाम मार्ग पर इसका परीक्षण किया गया। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की गति 110 किमी प्रतिघंटा तक पहुंच गई। फास्ट ट्रेनों को अहमदाबाद से भुज की यात्रा में लगभग 6.5 घंटे लगते हैं, किंतु वंदे मेट्रो ने 1.5 घंटे कम समय लिया।

12 कोच में 1150 यात्री

वंदे मेट्रो में एक बार में 1,150 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। मेट्रो ट्रेनों की तरह खड़े होकर भी यात्रा की जा सकती है। इस तरह एक बार में सीटिंग क्षमता से ज्यादा यात्री भी आना-जाना कर सकते हैं। ट्रेन में कई आधुनिक सुविधाएं हैं। माड्यूलर डिजाइन में इजेक्टर-आधारित बायो वैक्यूम टायलेट हैं। दिव्यांगों के लिए दोनों क्षोर पर अनुकूल शौचालय हैं।

बोगियों में एलईडी लाइट की व्यवस्था है। आउटलेट के साथ मोबाइल चार्जिंग साकेट है। मेट्रो की तरह एक कोच से दूसरे में यात्रियों

की आवाजाही को आसान बनाया गया है, ताकि अलग-अलग कोच में भीड़ ज्यादा न हो। ट्रेनों को आपस में टक्कर होने से बचाने के लिए कवच प्रणाली लगी हुई है। आग का पता लगाने और उसे बुझाने के लिए एरोसोल प्रणाली भी है।

इस साल क्यों ज्यादा सताएगी ठंड? WMO ने बताई असली वजह, IMD का भी अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले तीन दिनों में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। वहीं विश व मौसम संगठन ने पूर्वानुमान में कहा है कि इस साल कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

नई दिल्ली। भारत में इस वर्ष खूब गर्मी पड़ी और झमाझम बारिश ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े। बारिश ने कई राज्यों में खूब तबाही भी मचाई। पहाड़ों से लेकर मैदान तक कई जगह तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गुरुवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जहां आने वाले दिनों में अधिक वर्षा का अनुमान जताया है, वहीं विश्व मौसम संगठन (WMO) ने इस सर्दी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है।

उत्तरी भागों में कड़ाके की ठंड

विश्व मौसम संगठन (WMO) के विज्ञानियों का कहना है कि इस साल के अंत तक ला नीना (La Nina) का प्रभाव 60 प्रतिशत रहेगा। जिसकी वजह से इस वर्ष उत्तरी भागों में कड़ाके की ठंड तो पड़ेगी ही, साथ ही ठंड की अवधि भी अधिक होगी। ला नीना के डेवलप होने पर प्रशांत महासागर की सतह का टेम्प्रेचर कम हो जाता है। जब सतह का टेम्प्रेचर कम होगा तो ठंड भी अधिक होगी।

ला नीना का बढ़ता प्रभाव

बुधवार को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के लेटेस्ट अपडेट से पता चलता है कि सितंबर-नवंबर 2024 के दौरान ला नीना का प्रभाव 55 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। वहीं अक्तूबर 2024 से फरवरी 2025 तक यह संभावना बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। ला नीना के बढ़ते प्रभाव से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसलिए इस साल उत्तर भारत में सामान्य से अधिक ठंड पड़ सकती है।

जलवायु परिवर्तन पर निर्भर

हालांकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि ला नीना की स्थिति सामान्य से अधिक ठंडी सर्दियों का कारण बनेगी या नहीं। प्रत्येक ला नीना घटना के प्रभाव इसकी तीव्रता, अवधि, वर्ष के समय के आधार पर भिन्न होते हैं। हालांकि, ला नीना और एल नीनो जैसी प्राकृतिक रूप से होने वाली जलवायु घटनाएं जलवायु परिवर्तन पर निर्भर होती हैं।

मिठाई का पैकेट मे दो लाख, कलेक्टर को रिश्वत

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: सीमेंट कंपनी की अधिकारी मिठाई के पैकेट में रिश्वत दे रहा था। बाबू नौकरी पाने के लिए बड़ी रकम देता था। यह कोई क्लर्क या निम्न स्तर का कर्मचारी नहीं था, बल्कि बच्चे ने सीधे जिलाधिकारी को पकड़ लिया। एक और दिलचस्प बात ये है कि रिश्वत की रकम जिला कलेक्टर को मिठाई के पैकेट में दी गई थी।और उसने सोचा कि अगर उसने जिला कलेक्टर को पकड़ लिया, तो काम में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वह बेवकूफ बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ही भिजिलेंस ने सीनियर अधिकारी को पकड़ लिया। ऐसी घटना को लेकर शहर में खूब चर्चा हो रही है। जिलाधिकारी को रिश्वत की जांच करना महंगा पड़ गया। बरगढ़ जिले के कलेक्टर को रिश्वत देने के आरोप में एक सीमेंट कंपनी के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। कल जब एक व्यक्ति बरगढ़ जिला कलेक्टर से मिला तो उन्होंने एक किताब के साथ मिठाई का पैकेट भी दिया। बरगढ़ के जिला कलेक्टर को संदेह हुआ और उन्होंने पैकेट की जांच करने के लिए पियोन को बुलाया। वहीं निरीक्षण के दौरान 500 पीस के 4 बंडल निकले। जिसमें पता चला कि कुल 2 लाख रुपये थे। जिलाधिकारी ने तत्काल इसकी सूचना भिजिलेंस को दी। शख्स को भिजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति ने बरगढ़ जिला मजिस्ट्रेट को 2 लाख रुपये की रिश्वत दी थी, वह एक सीमेंट निर्माता कंपनी में उच्च पदस्थ अधिकारी राम बैभव कटू था। हालाँकि, यह व्यक्ति बारगढ़ जिला कलेक्टर को 2 लाख रुपये से भरा मिठाई का पैकेट क्यों दे रहा था, इसका कारण स्पष्ट नहीं है।

एक शाम गौमाता के नाम विशाल भजन संध्या में झूमे गोभक्त

परिवहन विशेष न्यूज

हैदराबाद। बीरमगुडा अमीनपुर स्थित श्री ब्रमराबा मल्लीकार्जुन स्वामी गौशाला में एक शाम गौमाता के नाम जागरण का आयोजित किया । आयोजक राजुराम कुमावत ने राजस्थान से आए प्रसिद्ध भजन गायक गजेन्द्र राव व शैतान सिंह जागरण का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। उसके बाद गायकों ने राजस्थानी लोक भजनों की प्रस्तुतियां देकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया।बाबा रामदेव जी रूणेचा सु पधारिया, भजनों से किया गोमाता की महिमा की महिमा का बखान,देर रात तक बही भक्ति की सरिता मंच संचालक ओम विशनोई ने किया । शुभ स्थल पर माह प्रसादी की व्यवस्था थी । बाबा रामदेव मंडली द्वारा प्रतिदिन में एक हरा घास गाड़ी की घोषणा कि। आयोजक मारवाड़ी मित्र मंडल श्री राम नगर कोण्डापुर द्वारा सभी गौभक्त का सम्मान किया था। रक्तदान शिविर में 60 युनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम में जैतारण से पधारे राकेश गेहलोत का भव्य सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी नेता रमेश अन्ना व राजु अन्ना का राजस्थानी साफा पहनाकर सम्मान किया गया। दोनों नेताओं ने सर्व समाज के लिए श्मशानघाट कि जमीन भेंट की गई। ट्रस्ट के पदाधिकारी सोहनलाल दामी, बिट्टल, सुखदेव जोशी,दामोदर रेड्डी,राजु तिवारी कोमल कठोरी, सर्व समाज अध्यक्ष एवं सचिव समाज बन्धु को राजस्थानी साफा पहनाकर सम्मान किया। श्री ब्रमरांबा मल्लीकार्जन स्वामी गौशाला एवं गैर मंडली प्रेमनगर, हफीज़पेट, माधापुर, टी.एन.जी. कॉलोनी, विवेकानंद कॉलोनी, अल्कापुर,मनिकोण्डा, मस्जिदबंडा,गवलीदोड्डी,हैदराबाद समस्त गौभक्त ने दान पुण्य का लाभ लिया।

जम्मू-कश्मीर में चुनाव के दौरान हमले की फिराक में आतंकी, खुफिया रिपोर्ट ने चौंकाया; क्या कदम उठाएगा EC?

जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। चुनाव में आतंकियों के बाधा डालने से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग अलर्ट मोड में है। चुनाव आयोग सुरक्षा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव की तैयारियों के लिए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने को कहा गया है।

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में आतंकियों के बाधा डालने से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट और अलर्ट के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी अब अलर्ट मोड में आ गया है। वह ऐसी किसी कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गया है। आयोग इस दौरान राज्य के सुरक्षा हालात पर जहां चौबीसों घंटे नजर रख रहा है, वहीं अपने आला अधिकारियों की एक टीम को भी राज्य के दौरे पर भेजा है। जो इन दिनों सभी जिलों की चुनावी तैयारियों के साथ सुरक्षा इंतजामों को भी जांचने में जुटी है।

18 सितंबर को होगा मतदान

राज्य में पहले चरण की 24 विधानसभा सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान होना है। आयोग ने इसके साथ ही राज्य के सुरक्षा इंतजामों को भी और कड़ा किया है। साथ ही प्रत्येक विधानसभा में सुरक्षा इंतजामों पर नजर रखने के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षकों की भी तैनाती दी है।

चुनाव को लेकर खुफिया अलर्ट

सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने सुरक्षा इंतजामों को जांचने की यह प्रक्रिया चुनाव में बाधा डालने को लेकर लगातार मिल रहे खुफिया अलर्ट के बाद शुरू की है। इस दौरान प्रत्येक विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की सुरक्षा को जांचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिलों में सुरक्षा इंतजामों के लिहाज से एक मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों के शीर्ष पदाधिकारियों को किसी क्षेत्र में प्रचार के लिए जाने से पहले स्थानीय प्रशासन को उसकी जानकारी देनी होगी।

तीन चरणों में वोटिंग

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने तीन चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए 25 सितंबर को और तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए एक अक्टूबर को मतदान होगा। जबकि इसके नतीजे अब आठ अक्टूबर को आएंगे।

राष्ट्रीयता और एकता की भावना जगाता हैं पवित्र गणेशोत्सव पर्व : वरिष्ठ समाजसेवी चन्द्रवीर सिंह फौजदार

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। गणेश चतुर्थी सम्पूर्ण हिंदू धर्म के लिए एक अति महत्वपूर्ण त्योहार है। आज देश गणेशोत्सव की भक्ति में लीन है। गणेश चतुर्थी का यह त्यौहार पूरे भारत में बड़े हर्ष और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा हैं। यह 10 दिवसीय विशाल उत्सव नदियों या झीलों में मूर्तियों के विसर्जन के साथ समाप्त होता है, जो भगवान गणेश की कैलाश पर्वत पर वापसी का भी प्रतीक है।

इस शुभ अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी चन्द्रवीर सिंह फौजदार ने सभी देशवासियों को श्रीगणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारा भारत पर्व-उत्सवों का देश है, और गणेश चतुर्थी उन्हीं विशेष उत्सवो में से एक है। पूरे भारत में भगवान गणेश के जन्मदिन के इस उत्सव को उनके भक्त बहुत उत्साह और धूमधाम के साथ मना रहें हैं। इसीलिए हमारा भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषता के कारण दुनियां में एक अलग पहचान रखता है। यही सांस्कृतिक विशेषता हमारे देश को श्रेष्ठता प्रदान करती हैं, इस विशेषता के दर्शन तीज त्यौहार, उत्सव, परंपराओं में होते है। इसी तरह की सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता भारत में दस दिवसीय गणेश उत्सव में नज़र आती हैं। इसीलिए यह उत्सव किसी विशेष जाति, वर्ग का नहीं होकर राष्ट्रीय उत्सव नजर आता है। गणेश उत्सव ने देश की राष्ट्रीय चेतना जगाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पवित्र गणेशोत्सव पर्व राष्ट्रीयता और एकता की भावना जगाता हैं। इस उत्सव की खास बात यह है की यह समाज के सभी वर्गों में समान उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आर्थिक मतभिन्नता के परे इस उत्सव में गजब की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता के दर्शन होते है। आजाद भारत में भी गणेश उत्सव राष्ट्रीयता एकता, सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बना हुआ है। गणेश उत्सव सांस्कृतिक रूप से भारतीय जनमानस में एकता

स्थापित करने का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। इसलिए राष्ट्रहित और हिन्दुहित के लिय हम सभी हिन्दुओं को लोकमंगल व राष्ट्रमंगल के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करना होगा। ताकि हम सभी मिलकर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सकतें हैं। क्योकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है, जब सभी ग़रीब अमीर हिन्दू एकजुट होकर रहेंगे और हिन्दू समाज को बांटने वाली देश विरोधी ताकतों से सतर्क और सावधान रहकर इनका बहिष्कार करेंगे तभी सही मायने में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की पूजा सार्थक होगी।

श्री फौजदार ने आगे कहा, हे विघ्नेश्वर, वर देने वाले सभी देवताओं को प्रिय, लम्बोदर, कलाओं से परिपूर्ण, जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले और वेद तथा यज्ञ से विभूषित माँ पार्वती के प्रिय पुत्र, बुद्धि एवं समृद्धि के आराध्य देव भगवान श्री गणेशजी की सभी पर कृपा हो और सभी के जीवन में सदैव उत्साह, आनंद, उल्लास का वास हो और हर घर-आंगन में शुभता और मांगल्य की वर्षा हो यही हमारी कामना है। श्री गणेश जी सभी को बुद्धि एवं समृद्धि प्रदान करें, सभी के दुखों का नाश करें और सभी के जीवन में खुशियां बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री गणेश जी सभी को सुख, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें और श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। समस्त देशवासियों को पावन पर्व श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

कविता : अजनबी कौन हो तुम?

अजनबी कौन हो तुम?
मैं बात कर रही हूँ और मौन हो तुम।

क्या, आंखों-आंखों में ही सब कहोगे?
अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहोगे।
मुझे समझ नहीं आया तो क्या करोगे?
तब तो मौन व्रत तोड़ोगे।

अजनबी कौन हो तुम?
मैं बात कर रही हूँ और मौन हो तुम।

क्या, हाथों में हाथ ले दोगे मेरा साथ?
क्या, ऐसी भी होती है कभी मुलाकात?
ये कैसा रिश्ता है मौन में भी पिसता है?
क्या तू कोई फरिश्ता है?

अजनबी कौन हो तुम?
मैं बात कर रही हूँ और मौन हो तुम।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
31, संजय नगर, इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023